सोमवार
02 नवम्बर 2026
● देहरादून
● वर्ष 34
● अंक 281
● पृष्ठ 8
● मूल्य ₹ 1.00

34 साल से देहरादून का विश्वास

दून वैली मेल

सांध्य दैनिक

आर.एन.आई. : 59626/94 email: doonvalley_news@yahoo.com Website: dunvalleymail.com डीएवीपी से मान्यता प्राप्त

मुख्यमंत्री ने किया 'देवभूमि परिवार पोर्टल' का शुभारंभ

◆विकसित भारत के संकल्प में महत्वपूर्ण योगदान देगा उत्तराखंडः मुख्यमंत्री

संवाददाता

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैम्प कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में 'देवभूमि परिवार पोर्टल' का शुभारंभ तथा 'विकसित उत्तराखंड विजन-2047' का विमोचन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये दोनों पहलें प्रदेश में सुशासन को मजबूत बनाने, सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाने और उत्तराखंड के दीर्घकालिक विकास को स्पष्ट दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।



मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी सरकार की सफलता का वास्तविक पैमाना केवल योजनाएं बनाना नहीं, बल्कि उनका लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना और उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना है। कई बार जानकारी के अभाव में पात्र व्यक्ति सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं। वहीं, नागरिकों को एक ही जानकारी के लिए बार-बार दस्तावेज देने और विभिन्न विभागों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। देवभूमि परिवार पोर्टल के माध्यम से इन समस्याओं को कम करने तथा सरकारी सेवाओं को अधिक सरल, पारदर्शी और नागरिक-केंद्रित बनाने का प्रयास किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री ने बाबा केदार की पावन भूमि से कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा। उनके इन शब्दों से प्रेरणा लेते हुए राज्य सरकार उत्तराखंड को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि विकसित उत्तराखंड विजन-2047 केवल लक्ष्यों का दस्तावेज नहीं, बल्कि प्रदेश के समग्र विकास की दिशा तय करने वाली कार्ययोजना है। इसकी सफलता के लिए सभी विभागों और जनपदों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप कार्ययोजना बनाकर समयबद्ध तरीके से कार्य करना होगा।

प्रमुख सचिव ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से योजनाओं की निगरानी, लाभार्थियों की आवश्यकताओं का आकलन तथा बजट और सरकारी संसाधनों का बेहतर नियोजन संभव होगा। इसके प्रभावी संचालन के लिए राज्य स्तर पर 'देवभूमि परिवार प्राधिकरण' तथा जिला स्तर पर 'जिला देवभूमि परिवार अधिकारी' की व्यवस्था प्रस्तावित है। उन्होंने बताया कि विजन में कृषि, पर्यटन, उद्योग, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कौशल विकास, कनेक्टिविटी और पर्यावरण संरक्षण को विशेष महत्व दिया गया है। वर्ष 2047 तक राज्य की स्थापित ऊर्जा क्षमता को लगभग 22 हजार मेगावाट तक बढ़ाने तथा वन आच्छादन को 46.6 प्रतिशत तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। विजन में वर्ष 2030, 2035, 2040, 2047 और 2050 के लिए अलग-अलग लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, जिनके आधार पर विभागीय कार्ययोजनाएं तैयार करने और प्रगति की नियमित समीक्षा करने की व्यवस्था पर जोर दिया गया है।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी एवं खजान दास, विधायक श्रीमती सविता कपूर, सेतु आयोग के सलाहकार दिनेश अग्रवाल, मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सेतु आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शत्रुघ्न सिंह, नीति आयोग की कार्यक्रम निदेशक डॉ. सोनिया पंत, आदित्य कुमार सहित जनप्रतिनिधिगण एवं शासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। विभिन्न जनपदों के जिलाधिकारी एवं जिलास्तरीय अधिकारी वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में जुड़े।

भतीजे ने की चाचा-चाची की हत्या!

हमारे संवाददाता

बागेश्वर। गरुड़ तहसील के नरगोड़ी गांव में आज सुबह दोहरे हत्याकांड की सूचना से हड़कंप मच गया। यहां देर रात एक युवक ने अपने चाचा और चाची पर लोहे की रॉड से हमला कर दिया। गंभीर चोटों के चलते दोनों की मौत हो गई। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया। पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी के लिए चार टीमें गठित कर तलाश तेज कर दी है।



जानकारी के अनुसार गोविंद बल्लभ खोलिया ने देर रात अपने चाचा पूरन चंद्र खोलिया और चाची भगवती देवी पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ हमला किया। हमले में दंपती गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के दौरान एक महिला ने किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। घटना की सूचना मिलने के बाद घायल दंपती को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) बैजनाथ ले जाया गया। हालांकि, दोनों की हालत बेहद गंभीर थी। चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू की। वारदात के बाद से आरोपी गोविंद बल्लभ खोलिया फरार है। पुलिस उसकी तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। कोतवाली प्रभारी कैलाश नेगी के मुताबिक, आरोपी की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की चार टीमें गठित की गई हैं। फिलहाल हत्या के पीछे की वजह स्पष्ट नहीं हो सकी है। पुलिस मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और आरोपी की तलाश जारी है।

दून वैली मेल

संपादकीय

वोटर लिस्ट से खिलवाड़, लोकतंत्र पर वार

चुनाव में धांधली केवल मतदान केंद्र पर नहीं होती, उसकी शुरुआत मतदाता सूची से भी हो सकती है। किसी पात्र मतदाता का नाम जानबूझकर काट देना, अपात्र नाम को सूची में बनाए रखना या नियमों को ताक पर रखकर मतदाता विवरण में बदलाव करना लोकतंत्र की जड़ों पर चोट है। मतदान का अधिकार तभी सार्थक है, जब मतदाता का नाम सूची में सुरक्षित हो और उसे बिना किसी बाधा के अपने मताधिकार का प्रयोग करने का अवसर मिले। इसलिए मतदाता सूची में जानबूझकर गड़बड़ी करने वालों के विरुद्ध निलंबन और दंडात्मक कार्रवाई की व्यवस्था को गंभीरता से लागू करना आवश्यक है। हालांकि, चुनाव आयोग के फैसले और दंड संबंधी प्रविधानों का सटीक दायरा आधिकारिक आदेश से ही स्पष्ट होना चाहिए। लोकतंत्र की विडंबना देखिए कि चुनाव में एक-एक वोट की अहमियत पर राजनीतिक दल बड़ी-बड़ी बातें करते हैं, लेकिन उसी वोट की पात्रता तय करने वाली मतदाता सूची में त्रुटियां सामने आने पर जिम्मेदारी से बचने की कोशिश भी होती है। मतदाता सूची में नाम होना किसी नागरिक पर एहसान नहीं, उसका लोकतांत्रिक अधिकार है। इस अधिकार की रक्षा करना चुनावी तंत्र की जिम्मेदारी है। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी अपने पद का दुरुपयोग करके इस व्यवस्था को प्रभावित करता है, तो उसे सामान्य प्रशासनिक लापरवाही मानकर छोड़ना लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ समझौता होगा। चुनाव आयोग की सख्ती का संदेश स्पष्ट होना चाहिएकृमतदाता सूची किसी अधिकारी की निजी जागीर नहीं है और न ही इसे राजनीतिक सुविधा के अनुसार बदलने की छूट दी जा सकती है। पात्र मतदाता का नाम हटाने या किसी अपात्र प्रविष्टि को जानबूझकर बनाए रखने जैसी अनियमितताएं प्रमाणित होती हैं, तो दोषी के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। केवल चेतावनी देकर मामला निपटा देना पर्याप्त नहीं होगा। जहां कानून दंड का प्रविधान करता है, वहां उसका निष्पक्ष और समान रूप से पालन भी होना चाहिए। लेकिन कार्रवाई का भय पैदा करना ही पर्याप्त नहीं है। असली सवाल यह है कि ऐसी गड़बड़ियां होती कैसे हैं और उन्हें रोकने के लिए व्यवस्था कितनी सक्षम है? मतदाता सूची के पुनरीक्षण में यदि बड़ी संख्या में नामों का सत्यापन किया जा रहा है, तो हर नाम के साथ पर्याप्त सावधानी बरतनी होगी। तकनीकी त्रुटि, दस्तावेजों की कमी और जानबूझकर की गई हेराफेरी के बीच स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। बिना जांच किसी को दोषी ठहराना भी उतना ही अनुचित है, जितना प्रमाणित गड़बड़ी पर आंखें मूंद लेना। विशेष गहन पुनरीक्षण जैसी व्यापक प्रक्रियाओं में यह चुनौती और गंभीर हो जाती है। बड़ी संख्या में मतदाताओं के विवरण की जांच करते समय प्रशासनिक सुविधा को नागरिक के अधिकार से ऊपर नहीं रखा जा सकता। किसी व्यक्ति का नाम सूची से हटाना महज एक आंकड़ा कम करना नहीं है। इसका सीधा असर उसके मतदान के अधिकार पर पड़ सकता है। इसलिए नाम हटाने की प्रक्रिया में निर्धारित नियमों, उचित सत्यापन, सूचना और दावा-आपत्ति के अवसरों का पालन अनिवार्य होना चाहिए। किसी पात्र नागरिक को केवल इसलिए अपने मताधिकार से वंचित नहीं होना चाहिए कि वह समय पर किसी जटिल प्रशासनिक प्रक्रिया को पूरा नहीं कर पाया। इस मामले में राजनीतिक दलों की जवाबदेही भी तय होनी चाहिए। मतदाता सूची में गड़बड़ी का आरोप लगाकर राजनीतिक लाभ उठाना जितना आसान है, प्रमाणों के साथ शिकायत दर्ज कराना और निष्पक्ष जांच में सहयोग करना उतना ही जरूरी है। चुनाव आयोग को भी किसी शिकायत को केवल राजनीतिक बयान मानकर खारिज नहीं करना चाहिए। आरोप चाहे सत्ता पक्ष लगाए या विपक्ष, जांच का पैमाना एक ही होना चाहिए। लोकतंत्र में चुनावी संस्थाओं की विश्वसनीयता आरोपों के शोर से नहीं, तथ्यों और निष्पक्ष कार्रवाई से मजबूत होती है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि मतदाता सूची की शुद्धता के नाम पर किसी वर्ग, समुदाय, क्षेत्र या राजनीतिक विचारधारा से जुड़े नागरिकों के साथ भेदभाव न हो। नियम सबके लिए समान हों और किसी भी पात्र मतदाता को अनावश्यक संदेह के आधार पर परेशान न किया जाए। पारदर्शिता का अर्थ केवल नामों की जांच करना नहीं, बल्कि हर बदलाव का स्पष्ट आधार उपलब्ध कराना और प्रभावित नागरिक को अपनी बात रखने का अवसर देना भी है। चुनाव आयोग को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मतदाता अपने नाम की स्थिति आसानी से जांच सकें, त्रुटि होने पर समयबद्ध सुधार करा सकें और अनुचित विलोपन के विरुद्ध प्रभावी शिकायत दर्ज कर सकें। साथ ही, मतदाता सूची तैयार करने वाले अधिकारियों के काम का नियमित परीक्षण हो तथा जहां जानबूझकर नियमों का उल्लंघन प्रमाणित हो, वहां जिम्मेदारी तय करने में देर न की जाए। तकनीक, निगरानी और जवाबदेही का ऐसा तंत्र विकसित करना होगा, जिसमें गलती पकड़ना आसान और गड़बड़ी छिपाना मुश्किल हो। आखिरकार, निष्पक्ष चुनाव का दावा तभी विश्वसनीय होगा, जब चुनाव की पहली सीढ़ी यानी मतदाता सूची ही निष्पक्ष हो। मतदान केंद्र पर सुरक्षा बढ़ाने और चुनावी आचार संहिता लागू करने का कोई अर्थ नहीं, यदि किसी पात्र नागरिक का नाम सूची में ही नहीं है। मतदाता सूची में गड़बड़ी करने वालों पर कार्रवाई इसलिए जरूरी है कि लोकतंत्र में किसी अधिकारी, कर्मचारी या राजनीतिक दल को नागरिक के मताधिकार से खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। लोकतंत्र में मतदाता का वोट सत्ता की ताकत तय करता है, इसलिए उस वोट तक पहुंचने का रास्ता किसी भी कीमत पर बाधित नहीं होना चाहिए। चुनाव आयोग की सख्ती तभी सार्थक होगी, जब वह केवल दंड का संदेश न दे, बल्कि यह भरोसा भी कायम करे कि हर पात्र मतदाता का नाम सुरक्षित रहेगा, हर शिकायत की निष्पक्ष जांच होगी और दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं होगा। मतदाता सूची से खिलवाड़ करने वालों के लिए सख्ती जरूरी है, लेकिन उससे भी जरूरी है ऐसी निष्पक्ष व्यवस्था, जिसमें लोकतंत्र के सबसे बुनियादी अधिकार की रक्षा किसी अपवाद के बजाय नियम बने।

चुनावी रंग में रंगी देवभूमि

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की औपचारिक घोषणा भले ही अभी नहीं हुई है, लेकिन प्रदेश की सियासत में चुनावी बिगुल बज चुका है। मौसम में बढ़ती ठंड के बीच राजनीतिक पारा चढ़ने लगा है। सत्ता में वापसी के लिए कांग्रेस सड़क पर उतरकर सरकार को घेरने की रणनीति बना रही है, तो भाजपा विपक्ष के आंदोलन को राजनीतिक अवसरवाद और अराजकता से जोड़कर जवाबी हमला बोल रही है। कांग्रेस की न्याय यात्रा के जवाब में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ यात्रा ने प्रदेश की राजनीति को सीधे चुनावी मुकाबले की ओर मोड़ दिया है।

यह लड़ाई केवल दो यात्राओं की नहीं है। इसके केंद्र में जनता के बीच अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता स्थापित करने, विरोधियों की रणनीति को कमजोर करने और वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले माहौल अपने पक्ष में बनाने की कोशिश है। दोनों प्रमुख दल जानते हैं कि चुनाव की घोषणा के बाद प्रचार की रफ्तार बढ़ाना पर्याप्त नहीं होगा। जनता के मन में जगह बनाने के लिए उससे पहले ही मुद्दों, नारों और राजनीतिक संदेशों की जमीन तैयार करनी होगी।

कांग्रेस अपनी न्याय यात्रा के जरिए प्रदेश सरकार को बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, भर्ती प्रक्रियाओं पर उठे सवालों, कानून-व्यवस्था और जनसमस्याओं के मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रही है। पार्टी की रणनीति सरकार के खिलाफ असंतोष को राजनीतिक समर्थन में बदलने की है। कांग्रेस चाहती है कि स्थानीय समस्याओं को लेकर उठने वाली आवाजें केवल विरोध प्रदर्शन तक सीमित न रहें, बल्कि उन्हें भाजपा सरकार के विरुद्ध एक व्यापक जनमत का रूप दिया जाए। दूसरी ओर, भाजपा ने लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ का नारा देकर कांग्रेस के आंदोलन की राजनीतिक धार कुंद करने की कोशिश

◆कांग्रेस की न्याय यात्रा के जवाब में भाजपा की लोकतंत्र बचाओ, अराजकता हटाओ यात्रा
◆सड़कों पर सियासी शक्ति प्रदर्शन, 2027 की सत्ता के लिए अभी से बिछने लगी बिसात
◆भाजपा और कांग्रेस ने प्रदेश की राजनीति को सीधे चुनावी मुकाबले की ओर मोड़ दिया

की है। भाजपा का संदेश है कि विपक्ष जनसमस्याओं के समाधान के बजाय राजनीतिक माहौल बनाने में जुटा है। इस जवाबी अभियान के जरिए पार्टी कांग्रेस को कठघरे में खड़ा करने और अपने कार्यकर्ताओं को चुनावी मोर्चे पर सक्रिय करने का प्रयास कर रही है।

इस तरह दोनों दलों ने अपने-अपने राजनीतिक आख्यान गढ़ने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस सरकार की जवाबदेही को चुनावी मुद्दा बनाना चाहती है, जबकि भाजपा विपक्ष के विरोध की मंशा पर सवाल उठाकर राजनीतिक बढ़त हासिल करने की कोशिश में है। उत्तराखंड में लगातार दूसरी बार सत्ता हासिल करने के बाद भाजपा के सामने अब तीसरी बार सरकार बनाने की चुनौती है। राज्य की राजनीति में सत्ता परिवर्तन की परंपरा रही है। ऐसे में वर्ष 2027 का चुनाव भाजपा के लिए केवल सरकार बचाने का मुकाबला नहीं, बल्कि इस धारणा को बदलने की परीक्षा भी होगा कि उत्तराखंड में हर पांच साल में सत्ता बदल जाती है।

भाजपा के पास केंद्र सरकार की योजनाओं, प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की लोकप्रियता, संगठनात्मक नेटवर्क और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व को चुनावी ताकत में बदलने का अवसर है। पार्टी विकास कार्यों, बुनियादी ढांचे, धार्मिक पर्यटन और केंद्र-राज्य के समन्वय को अपनी उपलब्धियों के रूप में जनता के सामने रख सकती है। लेकिन सत्ता में रहने का लाभ अपने साथ जवाबदेही भी लेकर आता है। बेरोजगारी, पलायन, ग्रामीण क्षेत्रों में सुविधाओं की कमी, भर्ती प्रक्रियाओं को लेकर युवाओं की नाराजगी और भ्रष्टाचार के आरोप जैसे सवालों पर सरकार को जनता के सामने अपना पक्ष रखना होगा। केवल विपक्ष को घेरने से इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा। भाजपा की चुनावी रणनीति की असली परीक्षा यही होगी कि वह अपने संगठन के उत्साह को सरकार के कामकाज के प्रति जनता के भरोसे में कितना बदल पाती है।

भाजपा और कांग्रेस के बीच तेज होते

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

2027 की जंग के लिए यूकेडी का 'युवा दांव'

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड की सियासत में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की आहट के साथ क्षेत्रीय राजनीति भी करवट लेने की कोशिश कर रही है। सत्ता की लड़ाई में अब तक भाजपा और कांग्रेस के बीच सिमटी दिखाई देने वाली राजनीति में उत्तराखंड क्रांति दल अपनी खोई जमीन तलाशने के लिए नई रणनीति के साथ आगे बढ़ रहा है। पार्टी का जोर युवा चेहरों को आगे लाने, नई पीढ़ी को नेतृत्व में भागीदारी देने और राज्य आंदोलन की मूल भावना को फिर से राजनीतिक विमर्श के केंद्र में लाने पर है।

यूकेडी के सामने चुनौती केवल चुनाव लड़ने की नहीं, बल्कि उस राजनीतिक पहचान को दोबारा स्थापित करने की है, जिसके आधार पर उत्तराखंड अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। राज्य आंदोलन की विरासत से जुड़ी पार्टी अब यह संदेश देने की कोशिश कर रही है कि उत्तराखंड की समस्याओं का समाधान प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियों, सामाजिक जरूरतों और स्थानीय आकांक्षाओं को समझने वाला नेतृत्व ही कर सकता है। युवा चेहरों को आगे करने की कवायद इसी रणनीति का हिस्सा मानी जा रही है।

उत्तराखंड की राजनीति में युवा मतदाता निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। रोजगार, भर्ती प्रक्रियाओं में पारदर्शिता, पलायन, स्थानीय संसाधनों पर अधिकार और पहाड़ों में बुनियादी सुविधाओं की कमी जैसे मुद्दे युवाओं के राजनीतिक दृष्टिकोण को प्रभावित करते हैं। यूकेडी इसी वर्ग के बीच अपनी पकड़ मजबूत करने की संभावना तलाश रही है। पार्टी के सामने अवसर यह है कि वह युवाओं की नाराजगी को केवल सरकार विरोधी भावना तक सीमित न रहने दे, बल्कि उसे एक स्पष्ट क्षेत्रीय राजनीतिक विकल्प में बदले। इसके लिए नए चेहरों को चुनावी मैदान में उतारना, स्थानीय स्तर

◆उत्तराखंड की सियासत में पुराने सियासी समीकरण तोड़ने की तैयारी
◆भाजपा-कांग्रेस के मुकाबले नई पीढ़ी को आगे करने की बनी रणनीति
◆आंदोलन की विरासत व पहाड़ी अस्मिता के सहारे विकल्प की तलाश

पर संगठन मजबूत करना और युवाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया में जगह देना महत्वपूर्ण होगा। हालांकि, युवा चेहरों को आगे करने का राजनीतिक संदेश तभी प्रभावी होगा, जब उन्हें केवल प्रचार और भीड़ जुटाने तक सीमित न रखा जाए। उम्मीदवार चयन, संगठन संचालन, नीति निर्माण और चुनावी रणनीति में उनकी वास्तविक भागीदारी ही इस पहल की विश्वसनीयता तय करेगी।

यूकेडी की सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी उत्तराखंड राज्य आंदोलन से उसका ऐतिहासिक जुड़ाव है। अलग राज्य की मांग के पीछे पहाड़ की विशिष्ट समस्याओं, स्थानीय रोजगार, प्रशासनिक विकेंद्रीकरण और क्षेत्रीय पहचान को प्रमुख आधार माना गया था। लेकिन राज्य गठन के बाद भी पलायन, रोजगार और पहाड़ी क्षेत्रों में विकास की असमानता जैसे सवाल बने हुए हैं। यही वह राजनीतिक जमीन है, जहां यूकेडी भाजपा और कांग्रेस दोनों को चुनौती देने की कोशिश कर सकती है। पार्टी यह सवाल उठा सकती है कि जिस राज्य की स्थापना स्थानीय आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हुई थी, वहां की नई पीढ़ी आज भी रोजगार के लिए दूसरे राज्यों की ओर क्यों देख रही है? पहाड़ी गांवों से पलायन क्यों जारी है? स्थानीय संसाधनों और नीतिगत फैसलों में उत्तराखंड के लोगों की भागीदारी कितनी प्रभावी है? इन सवालों पर जनसमर्थन हासिल करना और उनके व्यावहारिक समाधान सामने रखना यूकेडी के लिए महत्वपूर्ण होगा। केवल राज्य आंदोलन की स्मृतियों के सहारे नई पीढ़ी को लंबे समय तक जोड़े रखना मुश्किल है। युवा मतदाता विरासत का सम्मान करने के साथ भविष्य की स्पष्ट दिशा भी चाहते हैं।

भाजपा और कांग्रेस में भी युवा नेताओं और नए चेहरों की भूमिका लगातार महत्वपूर्ण होती रही है। ऐसे में केवल उम्मीदवारों की उम्र के आधार पर यूकेडी को अलग पहचान मिलना आसान नहीं होगा। पार्टी को यह दिखाना होगा कि उसके युवा चेहरे क्षेत्रीय समस्याओं की समझ, राजनीतिक इच्छाशक्ति और काम करने की क्षमता के मामले में क्या नया प्रस्तुत करते हैं। यदि यूकेडी स्थानीय मुद्दों पर सक्रिय युवा नेतृत्व तैयार करती है, गांवों और कस्बों में नियमित जनसंपर्क बढ़ाती है तथा

▶▶ शेष पृष्ठ 7 पर

विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज, 29 कार्यों के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

हरिद्वार(आरएनएस)। विधानसभा सामान्य निर्वाचन-2027 को लेकर जिला प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। जिलाधिकारी एवं जिला निर्वाचन अधिकारी मयूर दीक्षित ने निर्वाचन से जुड़ी व्यवस्थाओं के संचालन के लिए 29 कार्यों के तहत नोडल और सहायक नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की है। अधिकारियों को मतदान कार्मिकों की तैनाती, प्रशिक्षण, ईवीएम-वीवीपैट प्रबंधन, सुरक्षा, परिवहन और मतदाता जागरूकता सहित अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। मतदान और मतगणना कार्मिकों की व्यवस्था की जिम्मेदारी मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र को दी गई है। प्रशिक्षण व्यवस्था के लिए जिला कृषि एवं भूमि संरक्षण अधिकारी अमरेंद्र चौधरी और जिला शिक्षा अधिकारी अभिषेक शुक्ला को नोडल अधिकारी बनाया गया है। मतदान केंद्रों पर न्यूनतम सुविधाओं की व्यवस्था एडीएम वैभव गुप्ता देखेंगे। ईवीएम-वीवीपैट प्रबंधन के लिए अधिशासी अभियंता दिनेश कुमार और मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के लिए सीडीओ को जिम्मेदारी सौंपी गई है। वहीं, आदर्श आचार संहिता के अनुपालन की जिम्मेदारी नगर आयुक्त नंदन कुमार को दी गई है। निर्वाचन व्यय की निगरानी वरिष्ठ कोषाधिकारी अजय कुमार करेंगे। मीडिया एवं सूचना व्यवस्था जिला सूचना अधिकारी रती लाल शाह और कानून व्यवस्था एवं सुरक्षा योजना एडीएम जितेंद्र कुमार की निगरानी में रहेगी। इसके अलावा परिवहन, शिकायत निवारण, डाक मतपत्र, वीडियोग्राफी, पेयजल, सफाई, दिव्यांग मतदाताओं की सुविधा और आईटी व्यवस्था के लिए भी अधिकारी नामित किए गए हैं।

दीपावली पर पटाखों की बिक्री के लिए दो स्थान तय, 40 अस्थायी लाइसेंस होंगे जारी

अल्मोड़ा(आरएनएस)। दीपावली पर्व के दौरान आतिशबाजी और पटाखों की बिक्री के लिए जिला प्रशासन ने नगर क्षेत्र एवं उससे लगे आबादी वाले इलाकों में दो स्थल निर्धारित किए हैं। निर्धारित व्यवस्था के अनुसार एडम्स बालिका इंटर कॉलेज का खेल मैदान और एसएसजे विश्वविद्यालय परिसर स्थित सिमकनी मैदान में ही पटाखों की बिक्री की जा सकेगी। इसके लिए 5 से 9 नवंबर 2026 तक की अवधि तय की गई है। पटाखों की बिक्री के लिए व्यापारी और इच्छुक आवेदक निर्धारित प्रारूप में आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए आवेदन पत्र के साथ आधार कार्ड, नोटरीकृत शपथ पत्र, निर्धारित लेखाशीर्षक ००7०6०1०3०1०० में जमा धनराशि की प्रति और एक पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करना होगा। आवेदन कार्यालय उप जिलाधिकारी, सदर अल्मोड़ा में जमा किए जा सकेंगे। प्राप्त आवेदनों के आधार पर विस्फोटक अधिनियम, 2008 के नियम 84 में निर्धारित मानकों के अनुसार कुल 40 अस्थायी अनुज्ञप्तियां जारी की जाएंगी। एडम्स खेल मैदान में शेष अनुज्ञप्तिधारकों को दुकानें आवंटित की जाएंगी। दुकानों का आवंटन 4 नवंबर को अपराह्न दो बजे नगर निगम सभागार में लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। इस दौरान सहायक नगर आयुक्त मौजूद रहेंगे। प्रशासन ने प्रभारी निरीक्षक कोतवाली को निर्देश दिए हैं कि नगर क्षेत्र और उससे लगे आबादी वाले इलाकों में निर्धारित स्थलों के अलावा किसी अन्य स्थान या परिसर में आतिशबाजी एवं पटाखों की बिक्री, भंडारण और प्रदर्शनी न होने दी जाए।

परिवहन विभाग की कार्रवाई 120 वाहनों के चालान, 35 सीज

हरिद्वार(आरएनएस)। सड़क सुरक्षा को लेकर परिवहन विभाग ने जनपद में चेकिंग अभियान तेज कर दिया है। जिलाधिकारी के निर्देश पर चलाए गए अभियान में यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 120 वाहनों के चालान किए गए, जबकि 35 वाहनों को सीज किया गया। अभियान का नेतृत्व एआरटीओ (प्रवर्तन) नेहा झा और एआरटीओ (प्रशासन) निखिल शर्मा ने किया। अभियान के दौरान लग्जरी और स्लीपर बसों की तकनीकी स्थिति की विशेष रूप से जांच की गई। संभागीय निरीक्षक (प्राविधिक) आनंद वर्धन की मौजूदगी में बसों की फिटनेस, परमिट, आवश्यक दस्तावेज और तकनीकी मानकों का परीक्षण किया गया। इस दौरान 12 लग्जरी बसों के चालान किए गए और दो बसों को सीज किया गया।विभागीय टीम ने स्कूल बसों की भी जांच की। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए बसों की फिटनेस, सुरक्षा मानकों और जरूरी दस्तावेजों का सत्यापन किया गया। इसके अलावा अन्य यात्री और मालवाहक वाहनों को भी चेकिंग के दायरे में लिया गया। परिवहन विभाग ने वाहन संचालकों को फिटनेस, परमिट, बीमा सहित सभी जरूरी दस्तावेज अद्यतन रखने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले वाहन संचालकों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी।

वैधानिक सूचना

सुविज्ञ पाठकों से आग्रह है कि इस समाचार पत्र में प्रकाशित किसी भी विज्ञापन में दिए गए तथ्यों, शर्तों और दावों के प्रति वह खुद भी आश्वस्त हो लें। पाठकों से आग्रह है कि वह प्रकाशित विज्ञापन से प्रभावित होकर कोई कदम उठाने से पहले अपने स्तर पर भी स्वयं के संतुष्ट होने तक संपूर्ण व्यावहारिक जानकारी कर लें। भविष्य में किसी भी प्रकाशित विज्ञापन व लेख में निहित दावों या शर्तों को लेकर पाठकगण को कोई असुविधा या परेशानी होती है तो *सांध्य दैनिक दून वैली मेल* के मुद्रक, प्रकाशक या सम्पादक की कोई जवाबदेही नहीं होगी।

–प्रबंधक विज्ञापन

अब 'शब्दबाणों' की जंग

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की आहट के साथ ही भाजपा और कांग्रेस के बीच सियासी टकराव तेज होने लगा है। अभी चुनावी रण पूरी तरह सजा भी नहीं है, लेकिन दोनों प्रमुख दलों ने शब्दों के तीर चलाने शुरू कर दिए हैं। कभी भ्रष्टाचार के आरोप, कभी पुराने घोटालों की फाइलें और कभी नेताओं के बयानों पर पलटवार प्रदेश की राजनीति में अब विकास के दावों के साथ आरोपों की जंग भी तेज होती दिख रही है। दोनों दलों की कोशिश साफ है कि चुनावी मुकाबले में बढ़त बनाने के लिए प्रतिद्वंद्वी को कठघरे में खड़ा किया जाए।

गैरसैंण के भराड़ीसैंण में विधानसभा सत्र के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और भाजपा नेताओं के कांग्रेस पर हमलों ने इस सियासी टकराव को और धार दी। कांग्रेस सरकार के कार्यकाल से जुड़े कथित घोटालों और विवादों को उठाकर भाजपा ने विपक्ष को घेरने की कोशिश की। दूसरी ओर कांग्रेस सरकार के दावों, प्रदेश की मौजूदा समस्याओं और भाजपा के शासनकाल के कामकाज को लेकर सवाल उठा रही है। ऐसे में प्रदेश की राजनीति में आरोपों और जवाबी आरोपों का सिलसिला तेज होने के संकेत हैं।

भाजपा की रणनीति में कांग्रेस के पुराने शासनकाल को चुनावी बहस के केंद्र में रखना अहम दिखाई दे रहा है। पार्टी के नेता भ्रष्टाचार और कथित अनियमितताओं का हवाला देकर कांग्रेस की राजनीतिक विश्वसनीयता पर सवाल उठा रहे हैं। मुख्यमंत्री धामी के बयानों में भी कांग्रेस के पुराने कार्यकाल को निशाने पर लेने की कोशिश दिखाई दी है। भाजपा का संदेश है कि कांग्रेस को अपने शासनकाल के सवालों का जवाब देना चाहिए, जबकि मौजूदा सरकार अपने कामकाज और फैसलों के आधार पर जनता के बीच जाएगी।

भाजपा के लिए यह रणनीति इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि 2027 का चुनाव उसके सामने लगातार तीसरी बार सत्ता में वापसी की चुनौती लेकर आएगा। ऐसे में पार्टी कांग्रेस को केवल वर्तमान मुद्दों पर नहीं, बल्कि उसके पुराने कार्यकाल के आधार पर भी घेरना चाहती है। भ्रष्टाचार के आरोपों को चुनावी विमर्श में बनाए रखना भाजपा के लिए विपक्ष की राजनीतिक जमीन सीमित करने का माध्यम बन सकता है। हालांकि, आरोपों को राजनीतिक बयानबाजी से आगे ले जाने के लिए तथ्यों, जांच और कानूनी निष्कर्षों का महत्व बना रहेगा। किसी भी आरोप को प्रमाणित तथ्य के रूप में पेश करना उचित नहीं होगा। चुनावी बहस में जनता की दिलचस्पी केवल आरोप लगाने में नहीं, बल्कि यह जानने में भी होगी कि संबंधित मामलों में कार्रवाई कहां तक पहुंची और जवाबदेही किसकी तय हुई।

कांग्रेस के सामने भाजपा के आक्रामक तेवरों का जवाब देने के साथ अपनी चुनावी जमीन मजबूत करने की दोहरी चुनौती है। पार्टी को यह बताना होगा कि वह भाजपा

◆आरोप-प्रत्यारोप से गरमाई सियासत,एक- दूसरे को घेरने में जुटे दल
◆एक-दूसरे को कठघरे में खड़ा करने की फिराक में भाजपा-कांग्रेस
◆वार-पलटवार के दौर के साथ बढ़त बनाने की सियासी रस्साकस्सी

के आरोपों का तथ्यात्मक जवाब कैसे देगी और राज्य के मौजूदा सवालों पर उसका वैकल्पिक दृष्टिकोण क्या है। बेरोजगारी, पलायन, भर्ती प्रक्रियाओं पर उठते सवाल, महंगाई, ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की स्थिति और भ्रष्टाचार के आरोप ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष सरकार को घेर सकता है। लेकिन कांग्रेस के लिए केवल भाजपा के आरोपों को राजनीतिक दुर्भावना बताना पर्याप्त नहीं होगा। उसे अपने पुराने शासनकाल से जुड़े सवालों पर भी स्पष्टता दिखानी होगी। साथ ही, जनता के सामने यह भरोसा पैदा करना होगा कि सत्ता में आने का अवसर मिलने पर वह शासन और जवाबदेही के मामले में अलग दृष्टिकोण अपनाएगी।

कांग्रेस के लिए एक और चुनौती संगठनात्मक एकजुटता है। चुनावी मुकाबले में भाजपा की मजबूत संगठनात्मक तैयारी का सामना करने के लिए पार्टी को स्थानीय मुद्दों, जनसंपर्क और साझा रणनीति पर ध्यान देना होगा। बयानबाजी से राजनीतिक माहौल तो बनाया जा सकता है, लेकिन उसे मतदाताओं के समर्थन में बदलने के लिए जमीनी सक्रियता जरूरी होगी। भाजपा और कांग्रेस के बीच तेज होती बयानबाजी का एक पक्ष यह भी है कि इससे चुनाव से पहले राजनीतिक सक्रियता बढ़ती है। दोनों दल अपने समर्थकों को संदेश देते हैं, अपने मुद्दों को चर्चा में लाते हैं और प्रतिद्वंद्वी की कमजोरियों को उजागर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस पूरी कवायद में मूल सवाल पीछे छूटने का खतरा भी है। उत्तराखंड की जनता के सामने मौजूद चुनौतियों का समाधान क्या है?

राज्य गठन के बाद से रोजगार, पलायन, पहाड़ी क्षेत्रों में स्वास्थ्य और शिक्षा की उपलब्धता, किसानों की समस्याएं, आपदा प्रबंधन और स्थानीय संसाधनों पर आधारित अर्थव्यवस्था जैसे प्रश्न लगातार महत्वपूर्ण बने हुए हैं। मतदाता यह जानना चाहेंगे कि भाजपा इन मुद्दों पर अपने शासनकाल का क्या हिसाब देती है और कांग्रेस इनके समाधान के लिए कौन-सा ठोस विकल्प प्रस्तुत करती है। चुनावी राजनीति में शब्दों की धार का अपना महत्व है, लेकिन केवल तीखे बयानों से जनता का विश्वास हासिल नहीं किया जा सकता। भाजपा को अपने विकास संबंधी दावों के साथ जमीनी परिणामों का हिसाब देना होगा, जबकि कांग्रेस को सरकार की आलोचना के साथ व्यावहारिक विकल्प भी सामने रखने होंगे।

उत्तराखंड में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा और कांग्रेस के बीच मुकाबला अभी शुरुआती दौर में है, लेकिन बयानबाजी बता रही है कि दोनों दल चुनावी विमर्श पर पकड़ बनाने की कोशिश में जुट गए हैं। भाजपा कांग्रेस के अतीत को मुद्दा बनाना चाहती है, जबकि कांग्रेस के सामने वर्तमान सरकार के कामकाज को बहस के केंद्र में लाने की चुनौती है।

आने वाले दिनों में नेताओं के बयान, संगठनात्मक गतिविधियां और जनसभाएं इस टकराव को और तेज कर सकती हैं। लेकिन चुनावी लड़ाई का अंतिम फैसला इस आधार पर नहीं होगा कि किसने किस पर ज्यादा तीखा हमला किया। निर्णायक सवाल यह होगा कि किस दल के पास जनता की समस्याओं का विश्वसनीय समाधान, अपने दावों के समर्थन में तथ्य और उन्हें जमीन पर उतारने की राजनीतिक इच्छाशक्ति है। फिलहाल उत्तराखंड की सियासत में शब्दबाण चलने लगे हैं। अब देखना यह है कि यह जंग आरोपों के शोर तक सीमित रहती है या जनता के असल मुद्दों पर ठोस राजनीतिक बहस का रास्ता भी खोलती है।

सैंपलिंग के नाम पर व्यापारियों के उत्पीड़न का आरोप, सड़क पर उतरने की चेतावनी

अल्मोड़ा(आरएनएस)। मिठाई कारोबारियों के कथित उत्पीड़न के विरोध में व्यापार मंडल अल्मोड़ा ने मोर्चा खोल दिया है। धारानौला में आयोजित बैठक में मिठाई व्यापारियों ने खाद्य विभाग और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि त्योहारों के नजदीक आते ही सैंपलिंग के नाम पर व्यापारियों को अनावश्यक रूप से परेशान किया जाता है। व्यापार मंडल ने चेतावनी दी कि उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो व्यापारी एकजुट होकर सड़कों पर उतरेंगे। व्यापारियों ने कहा कि स्वच्छता और खाद्य पदार्थों की शुद्धता उनके व्यवसाय का अभिन्न हिस्सा है। वर्षों से कारोबार कर रहे व्यापारी अपनी प्रतिष्ठा और ग्राहकों के विश्वास के आधार पर व्यापार करते हैं। उन्होंने मेलों और अस्थायी फड़ों में बिकने वाली मिठाइयों की गुणवत्ता पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि नियमित दुकानदारों पर कार्रवाई का दबाव बनाया जाता है, जबकि वहां अपेक्षित निगरानी नहीं होती। बैठक में जिलाध्यक्ष सुशील साह ने व्यापारियों से एकजुट रहने और दुकानों में साफ-सफाई के साथ शुद्ध खाद्य सामग्री रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि किसी एक व्यापारी की गलती के लिए पूरे व्यापारी समाज को मिलावटखोर कहना उचित नहीं है। मिठाई विक्रेताओं को कथित रूप से %मीठा जहर% कहे जाने पर भी उन्होंने आपत्ति जताई। सुशील साह ने कहा कि नियमों का पालन करने के बावजूद किसी व्यापारी को अनावश्यक रूप से प्रताड़ित किया गया तो व्यापार मंडल संबंधित अधिकारियों का घेराव करेगा। जरूरत पड़ने पर व्यापारी सड़क पर उतरकर विरोध करेंगे। विजय भट्ट और अश्विन नेगी ने भी व्यापारियों के सम्मान और अधिकारों की लड़ाई में साथ देने का भरोसा दिलाया। व्यापारियों ने मांग की कि खाद्य सुरक्षा नियमों के तहत जांच और सैंपलिंग की प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और सम्मानजनक हो। बैठक में संयुक्त महामंत्री दिनेश मठपाल, जिला उपाध्यक्ष विजय भट्ट, जिला मंत्री नरेंद्र कुमार,वकुल साह, अश्विन नेगी, जीवन चन्द्र पन्त, आनन्द सिंह अधिकारी, पूरन महरा, अशोक सिंह, दीवान राम, दीवान मनराल, मनोज बिष्ट आदि व्यापारी मौजूद रहे।

गांजे के साथ महिला गिरफ्तार

संवाददाता

देहरादून। पुलिस ने गांजे के साथ महिला को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार डोईवाला कोतवाली पुलिस ने केशवपुरी बस्ती की तरफ जाने वाले रास्ते पर एक महिला को संदिग्ध अवस्था में घुमते हुए देखा तो उसको रूकने का इशारा किया। पुलिस को देख वह भाग खडी हुई। पुलिस ने पीछा कर उसको थोडी दूरी पर ही पकड लिया। तलाशी लेने पर पुलिस ने उसके कब्जे से एक किलो 296 ग्राम गांजा बरामद कर लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम सुलेखा पत्नी दिनेश साहनी निवासी केशवपुरी बस्ती बताया। पुलिस ने उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उसको न्यायालय में पेश किया जहां से उसको न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया।

दुकान का शटर तोडकर लैपटॉप चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने दुकान का शटर तोडकर वहां से लैपटॉप चोरी कर लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार माजरा निवासी अंकित सिंह ने बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी जीएमएस रोड पर दुकान है। आज जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो उसने देखा कि दुकान का शटर टूटा हुआ था तथा अन्दर से लैपटॉप गायब था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

घर की खिडकी तोडकर नगदी व कागजात चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने मकान की खिडकी तोडकर वहां से नगदी व स्कूटी की चाबी चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवालिक पुरम निवासी अंशुल पालीवाल ने बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि चोरों ने उसके मकान की खिडकी तोडकर वहां से पांच हजार रूपये नगद व स्कूटी की चाबी चोरी कर ली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

दुकान का ताला तोड जेवरात चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने दुकान का ताला तोड वहां से जेवरात चोरी कर लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार लक्खीबाग निवासी अश्विनी कुमार ने बसंत विहार थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी बल्लीवाला चौक पर सुनार की दुकान है। आज जब वह अपनी दुकान पर पहुंचा तो देखा कि उसकी दुकान का ताला टूटा हुआ था तथा अन्दर सं जेवरात व चांदी के सिक्के गायब थे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत

संवाददाता

देहरादून। वाहन की चपेट में आकर युवक की मौत हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

प्राप्त जानकारी के अनुसार मन्दाकिनी विहार निवासी राजकुमार ने रायपुर थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका बेटा अनिकेत उर्फ राहुल घर की तरफ पैदल आ रहा था। जब वह नालापानी रोड देवलोक कालोनी के पास पहुंचा तभी तेज रफ्तार से आ रहीं टाटा सफारी ने उसको अपनी चपेट में ले लिया जिससे उसके बेटे की मृत्यु हो गयी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

मकान का ताला तोड नगदी व दस्तावेज चोरी

संवाददाता

देहरादून। चोरों ने मकान का ताला तोड वहां से नगदी व दस्तावेज चोरी कर लिये। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार सिंचाई विभाग निवासी सुन्दर सिंह नेगी ने विकासनगर कोतवाली में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसका ढालीपुर सिंचाई विभाग में सरकारी आवास है। आज जब वह अपने आवास पर पहुंचा तो देखा कि मकान का ताला टूटा हुआ था तथा अन्दर सारा सामान अस्त व्यस्त पडा था। चोर उसके यहां से नगदी, एक फोन व दस्तावेज चोरी करके ले गये हैं। पुलिस ने मुदकाम दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

...और खुलने लगी सियासी दुकानें

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की उलटी गिनती शुरू होने से पहले ही प्रदेश का सियासी पारा चढ़ने लगा है। पांच साल तक राजनीतिक नेपथ्य में रहने वाले दल अब अचानक सक्रिय दिखाई देने लगे हैं। कहीं नई पार्टी के गठन की घोषणा हो रही है, कहीं पुराने क्षेत्रीय दल फिर से अपनी ताकत जुटाने में लगे हैं, तो कहीं नए राजनीतिक विकल्प के नाम पर जनता के बीच पहुंचने की तैयारी है। चुनावी मौसम नजदीक आते ही राजनीतिक गतिविधियों में आई इस तेजी ने एक बार फिर सवाल खड़ा कर दिया है कि प्रदेश की राजनीति में सक्रिय होने वाले ये दल वास्तव में जनता के मुद्दों की लड़ाई लड़ना चाहते हैं या चुनाव के आसपास अपनी राजनीतिक मौजूदगी दर्ज कराने की कवायद कर रहे हैं।

उत्तराखंड की राजनीति लंबे समय से भाजपा और कांग्रेस के बीच सत्ता के इर्द-गिर्द घूमती रही है। राज्य गठन के बाद से अब तक इन दोनों दलों ने बारी-बारी से सरकार बनाई है। इस दौरान उत्तराखंड क्रांति दल सहित कई क्षेत्रीय और छोटे राजनीतिक दलों ने तीसरे विकल्प के रूप में जगह बनाने की कोशिश की, लेकिन वे सत्ता की निर्णायक दौड़ में अपनी मजबूत उपस्थिति कायम नहीं कर सके। अब 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर राजनीतिक मैदान में नए खिलाड़ियों की आमद शुरू हो गई है।

चुनावी राजनीति का एक स्थापित दृश्य है। चुनाव नजदीक आते ही राजनीतिक दलों की सक्रियता बढ़ जाती है। प्रेसवार्ताएं होने लगती हैं, सरकार के खिलाफ बयान जारी होते हैं, नए राजनीतिक समीकरणों की चर्चाएं शुरू हो जाती हैं और जनता के बीच जाने के संकल्प लिए जाने लगते हैं। उत्तराखंड में भी यही तस्वीर उभरती दिखाई दे रही है। सवाल यह है कि जो दल पिछले वर्षों में बेरोजगारी, पलायन, भर्ती विवाद, पहाड़ों में स्वास्थ्य और शिक्षा की बदहाली, ग्रामीण अर्थव्यवस्था तथा स्थानीय संसाधनों से जुड़े सवालों पर लगातार सक्रिय नहीं दिखे, वह अब चुनावी मैदान में उतरकर जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्या उनके पास इन समस्याओं के समाधान का कोई ठोस खाका है, या फिर उनका मकसद केवल चुनावी मुकाबले में अपनी मौजूदगी दर्ज कराना है?

हालांकि, हर नए दल या राजनीतिक पहल को केवल चुनावी अवसरवाद मान लेना भी उचित नहीं होगा। लोकतंत्र में नए विकल्पों का उभरना स्वाभाविक है। लेकिन किसी राजनीतिक दल की विश्वसनीयता

◆पांच साल तक जनता के बीच नजर नहीं आए दल अब मैदान में सक्रिय
◆राजनीतिक विकल्पों की दस्तक के बीच भाजपा-कांग्रेस की बढ़ी चुनौतियां
◆पांच साल तक राजनीतिक नेपथ्य में रहने वाले दल भी अब हो गए सक्रिय

उसकी घोषणाओं से नहीं, बल्कि उसके संघर्ष, संगठन, निरंतर जनसंपर्क और जनता के मुद्दों पर किए गए काम से तय होती है। प्रदेश में नए राजनीतिक विकल्पों की चर्चा के पीछे जनता की अपेक्षाओं और असंतोष की भूमिका को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। रोजगार की तलाश में पलायन करते युवा, गांवों में घटती आबादी, पहाड़ी क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं की चुनौतियां और राजनीतिक दलों से बढ़ती जवाबदेही की मांग नए विकल्पों के लिए जमीन तैयार कर सकती हैं।

लेकिन उत्तराखंड में तीसरे विकल्प की राह आसान नहीं रही है। राज्य आंदोलन के दौरान क्षेत्रीय अस्मिता और स्थानीय हितों की राजनीति ने उत्तराखंड क्रांति दल को महत्वपूर्ण पहचान दी थी। इसके बावजूद क्षेत्रीय राजनीति उस जनसमर्थन को स्थायी चुनावी ताकत में नहीं बदल सकी, जिसकी उम्मीद राज्य आंदोलन के दौर में दिखाई देती थी। संगठनात्मक कमजोरियां, राजनीतिक बिखराव और व्यापक जनाधार बनाने में कठिनाइयां इसके पीछे महत्वपूर्ण कारण रहे हैं। अब नए राजनीतिक दलों और पुराने क्षेत्रीय संगठनों के सामने वही पुरानी चुनौती है। क्या केवल भाजपा और कांग्रेस के विरोध के आधार पर राजनीति करेंगे, या जनता के सामने शासन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, पलायन और विकास को लेकर कोई स्पष्ट वैकल्पिक माडल भी रखेंगे?

चुनाव से पहले छोटे दलों और नए राजनीतिक संगठनों की सक्रियता भाजपा और कांग्रेस के लिए चुनौती भी बन सकती है और अवसर भी। इसका वास्तविक असर इस बात पर निर्भर करेगा कि यह दल किन क्षेत्रों में मजबूत होते हैं, किन सामाजिक समूहों तक पहुंच बनाते हैं और कितने प्रभावी ढंग से मतदाताओं का विश्वास हासिल कर पाते हैं। यदि नए दल कुछ विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी जनाधार तैयार करते हैं, तो वह सीधे मुकाबले को प्रभावित कर सकते हैं। हालांकि, केवल राजनीतिक गतिविधियों या घोषणाओं के आधार पर यह निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी कि वह भाजपा या कांग्रेस के लिए निर्णायक चुनौती बन जाएंगे। चुनावी सफलता के लिए मजबूत संगठन, स्थानीय नेतृत्व, संसाधन, उम्मीदवारों की विश्वसनीयता और बूथ स्तर तक पहुंच जरूरी होती है।

भाजपा के पास संगठनात्मक ढांचा और सत्ता में रहने का अनुभव है, जबकि कांग्रेस सरकार के खिलाफ असंतोष को चुनावी समर्थन में बदलने की कोशिश करेगी। ऐसे में नए दलों के सामने दोनों राष्ट्रीय दलों से अलग अपनी पहचान स्थापित करने की कठिन परीक्षा होगी। चुनाव नजदीक आने के साथ राजनीतिक सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक है, लेकिन जनता को यह देखने का अधिकार है कि राजनीतिक दलों की प्राथमिकता क्या है। क्या बेरोजगार युवाओं के सवालों पर लगातार संघर्ष करेंगे? क्या पलायन से खाली होते गांवों के लिए ठोस नीति पेश करेंगे? क्या पहाड़ों में स्वास्थ्य और शिक्षा की सुविधाओं को मजबूत करने की योजना देंगे? क्या राज्य के संसाधनों और स्थानीय लोगों के अधिकारों पर स्पष्ट रुख अपनाएंगे?

इन सवालों का जवाब केवल चुनावी घोषणापत्र में नहीं, बल्कि दलों के पिछले

▶▶ शेष पृष्ठ 5 पर

शब्द सामर्थ्य -077

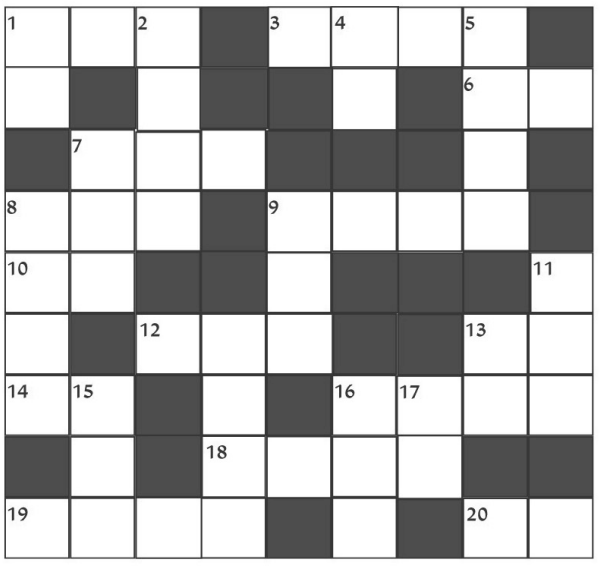
(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. चौड़ी और सपाट जमीन, रणभूमि 3. स्वरग्राम, संगीत के सात स्वरों का समूह 6. धूल का कण, किसी वस्तु का सूक्ष्मकण, धूल 7. हिम्मत, सामर्थ्य 8. अभ्यर्थना, रिसेप्शन, यथा अवसर पर पूछे जाने वाला मंगल कुशल 9. आपस का करार, निबटारा 10. वरदान, दुल्हा 12. भोग, ऐश्वर्य 13. कीमत, मूल्य 14. एक वाद्ययंत्र जिसे सपेरे बजाते हैं 16. समता, बराबरी 18. अश्लील, बेहुदा, अभद्र, घटिया 19. युक्ति, उपाय, ढंग 20. रिक्त, अपूर्ण।

ऊपर से नीचे

1. दोस्ती, मित्रता 2. अच्छी शिक्षा, नेक सलाह 4. बचाव, हिफाजत 5. मीठापन, मधुर होने का भाव 7. समुद्र 8. आत्मनिर्भर, जो दूसरे पर आश्रित न हो 9. रसवाला, रसदार 11. मां का बच्चों के प्रति प्रेम 13. खैरात, देने की क्रिया 15. दृष्टि, निगाह 16. वरिष्ठ, बुजुर्ग, चतुर 17. पराजय, हार।



शब्द सामर्थ्य क्रमांक 76 का हल

ला	लू	प्र	सा	द	या	द	व	
प		ति			र	क्ष	क	
र	ह	मा	न					आ
वा			मि	थु	न		दा	स
ह	वा	ला	त		सी	ता		पा
	न				ब	क	वा	स
औ	र	त		म		त		
ला		बे	च	ना		व	च	न
द	ह	ला		ना	ग	र		दी

हैलोवीन वीकेंड पर जश्न के बीच अमेरिका में कई शहरों में गोलीबारी, 6 की मौत

संवाददाता

नई दिल्ली। अमेरिका में हैलोवीन वीकेंड के दौरान जश्न के बीच कई शहरों में गोलीबारी की घटनाओं ने दहशत फैला दी। नाइटलाइफ और भीड़भाड़ वाले इलाकों में हुई इन घटनाओं में कम से कम छह लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जनों लोग घायल हुए हैं। डलास, बर्मिंघम, नेवार्क, ब्लूमिंगटन और फेयेटविले में फायरिंग की घटनाएं सामने आई हैं। पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और सभी मामलों की जांच की जा रही है। डलास में सबसे ज्यादा हिंसा हुई। पुलिस के मुताबिक, शहर के डीप एलम इलाके में शनिवार रात गोलीबारी की तीन अलग-अलग घटनाओं में चार लोगों की मौत हो गई, जबकि 15 लोग घायल हुए हैं। डीप एलम संगीत, रेस्तरां और नाइटलाइफ के लिए जाना जाता है।

डलास पुलिस प्रमुख डैनियल कोमोक्स ने बताया कि जांच की जा रही है कि शनिवार रात हुई तीनों घटनाओं का आपस में कोई संबंध है या नहीं। फिलहाल गोलीबारी के पीछे की वजह भी स्पष्ट नहीं हो पाई है।

अलबामा के बर्मिंघम में शनिवार रात मैजिक सिटी क्लासिक फुटबॉल मैच के बाद लीजन फील्ड स्टेडियम के बाहर गोलीबारी हुई। इस घटना में एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि आठ अन्य घायल हो गए। बर्मिंघम पुलिस विभाग के प्रमुख माइकल पिकेट के अनुसार, मैच खत्म होने के बाद अधिकांश दर्शक और परिवार स्टेडियम से जा चुके थे।

डेलावेयर राज्य के नेवार्क शहर में शनिवार को यूनिवर्सिटी ऑफ डेलावेयर कैंपस के पास गोलीबारी हुई। इसमें छह लोग घायल हो गए, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में फायरिंग के बाद लोग जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते दिखाई दिए।

इलिनोइस के ब्लूमिंगटन में रविवार सुबह हुई गोलीबारी में 19 साल की एक महिला की मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हुई है। इस घटना में छह और लोग भी घायल हुए हैं, हालांकि उन्हें गंभीर चोटें नहीं आई हैं। पुलिस ने अभी यह स्पष्ट नहीं किया है कि इन छह लोगों को चोटें किन परिस्थितियों में आईं।

अर्कांसस के फेयेटविले में रविवार सुबह गोलीबारी की घटना में छह लोग घायल हो गए। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक, शुरुआती जांच में सामने आया है कि गोलीबारी से पहले वहां किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। फिलहाल इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है।

दून में आयोजित 'वॉयस ऑफ नॉर्थ इंडिया' में रीता राणा बनीं फाइनलिस्ट

संवाददाता



देहरादून। 'वॉयस ऑफ नॉर्थ इंडिया' कार्यक्रम में गायिका श्रीमती रीता राणा ने अपनी सुरीली आवाज से समां बांध दिया।

आज यहां शहर के पटेलनगर स्थित होटल स्पैरो में आयोजित 'वॉयस ऑफ नॉर्थ इंडिया' कार्यक्रम में गायिका श्रीमती रीता राणा ने अपनी सुरीली आवाज से समां बांध दिया। उनकी गायकी ने कार्यक्रम में मौजूद लोगों का ध्यान आकर्षित किया। इस प्रतियोगिता में रीता राणा को फाइनलिस्ट के रूप में सम्मानित करते हुए ट्रॉफी प्रदान की गई। कार्यक्रम में देश और प्रदेश के विभिन्न स्थानों से प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। आयोजन को सफल बनाने में श्रेयान ठाकुर, शोभा बडोला और उनकी टीम का विशेष सहयोग रहा। संगीत और गायन से सजी इस शाम में प्रतिभागियों की प्रस्तुतियों ने कार्यक्रम को यादगार बनाया।

...और खुलने लगी सियासी दुकानें..

◀◀ पृष्ठ 4 का शेष

व्यवहार और वर्तमान गतिविधियों में भी तलाशना होगा। पांच साल तक निष्क्रिय रहने वाला कोई दल यदि चुनाव के कुछ महीने पहले जनता का हितैषी बनने का दावा करता है, तो उसके दावों की कसौटी उसका पुराना रिकार्ड भी होना चाहिए। उत्तराखंड की जनता ने राज्य निर्माण के लिए लंबा संघर्ष किया था। उस आंदोलन के पीछे केवल अलग राज्य का सपना नहीं, बल्कि बेहतर शासन, रोजगार, स्थानीय भागीदारी और पहाड़ों के संतुलित विकास की उम्मीद भी थी। इसलिए प्रदेश की राजनीति में नए दलों का उभरना तभी सार्थक होगा, जब वह इन अधूरे सवालों को अपनी राजनीति के केंद्र में रखेंगे। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले उत्तराखंड का राजनीतिक मैदान धीरे-धीरे सज रहा है। नए दल अपनी जगह तलाश रहे हैं, क्षेत्रीय संगठन फिर से ताकत जुटाने में लगे हैं और भाजपा-कांग्रेस के बीच भी राजनीतिक मुकाबला तेज होने की जमीन तैयार हो रही है। लेकिन चुनावी राजनीति में सक्रियता और जनाधार के बीच बड़ा अंतर होता है। प्रेसवार्ताओं, घोषणाओं और नारों से राजनीतिक चर्चा तो पैदा की जा सकती है, मगर जनता का विश्वास लंबे संघर्ष और ठोस काम से ही हासिल होता है। उत्तराखंड में अब सवाल केवल यह नहीं है कि चुनाव लड़ने के लिए कितनी पार्टियां मैदान में उतरेंगी। असली सवाल यह है कि इनमें से कितनी पार्टियां अगले पांच साल तक जनता के बीच रहेंगी, जो दल चुनाव के बाद भी बेरोजगारों, किसानों, महिलाओं, युवाओं और पहाड़ के गांवों के सवालों पर संघर्ष करेंगे, वही अपनी राजनीतिक विश्वसनीयता स्थापित कर पाएंगे। बाकी दलों की सक्रियता चुनावी मौसम की हलचल बनकर रह जाने का खतरा उठाएगी।

साइकिल रैली से दिया 'भ्रष्टाचार मुक्त समाज' और सतर्कता का संदेश

संवाददाता



देहरादून। सतर्कता जागरूकता सप्ताह के अवसर पर देहरादून साइक्लिंग क्लब एवं केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई), भ्रष्टाचार निरोधक शाखा, देहरादून के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को सतर्कता जागरूकता सामुदायिक साइकिल रैली का आयोजन किया गया। रैली का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों, विद्यार्थियों एवं युवाओं को भ्रष्टाचार के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक करना तथा समाज में ईमानदारी, पारदर्शिता, जवाबदेही और सत्यनिष्ठा के मूल्यों को बढ़ावा देना था।

रैली का शुभारंभ सीबीआई मुख्यालय, सीमाद्वार, देहरादून से हुआ। क्लब के उपाध्यक्ष मनिंदर सिंह ने रैली का फ्लैग ऑफ किया, साइकिल सवारों ने पंडितवाड़ी, प्रेमनगर, नंदा की चौकी, पौंधा, मझान, सैला होते हुए खाराखेत तक साइकिल यात्रा की और वापसी की। लगभग 35 किलोमीटर की इस जागरूकता यात्रा में करीब 32 साइकिल सवारों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। रैली का नेतृत्व वरिष्ठ साइकिल सवार सुरिंदर कुमार एवं जयन्ती प्रसाद गौड़ ने किया।

रैली के दौरान साइकिल सवारों ने स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी तथा अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में सतर्क रहने, ईमानदारी अपनाने और भ्रष्टाचार के विरुद्ध सजग नागरिक की भूमिका निभाने की शपथ ली।

इस अवसर पर सीबीआई के डीआईजी मनीष सुरती ने भ्रष्टाचार के विरुद्ध स्पष्ट संदेश देते हुए कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी परिस्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। उन्होंने नागरिकों से सतर्कता गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी करने तथा अपने आसपास होने वाली भ्रष्ट गतिविधियों की जानकारी संबंधित अधिकारियों को देने का आग्रह किया। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई के लिए जागरूक नागरिकों की भागीदारी अत्यंत महत्वपूर्ण है।

सीबीआई के डीएसपी अजय मिश्रा ने कहा कि सीबीआई विभिन्न शैक्षणिक एवं अन्य संस्थानों का दौरा कर रही है और आम नागरिकों तथा विद्यार्थियों को सतर्कता के प्रति जागरूक कर रही है। उन्होंने कहा कि समाज में भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक करना और उनमें नैतिक मूल्यों को विकसित करना आवश्यक है।

देहरादून साइक्लिंग क्लब के अध्यक्ष हरिसिमरन सिंह ने सीबीआई देहरादून एवं देहरादून साइक्लिंग क्लब को इस महत्वपूर्ण पहल के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त समाज अपने विकास, समानता और समृद्धि के लक्ष्यों को अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सकता है। आज आवश्यकता ऐसे जागरूक नागरिकों की है, जो अपने व्यक्तिगत जीवन में ईमानदारी अपनाएं और भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपनी जिम्मेदारी समझें।

उन्होंने आगे कहा कि देहरादून साइक्लिंग क्लब वर्ष 2013 से साइकिलिंग को बढ़ावा देने के साथ-साथ स्वस्थ जीवनशैली, पर्यावरण संरक्षण, नशामुक्त समाज, सड़क सुरक्षा एवं सामाजिक जागरूकता के लिए निरंतर कार्य कर रहा है। क्लब भविष्य में भी जनहित से जुड़े अभियानों में सक्रिय भागीदारी निभाता रहेगा।

रैली में शामिल साइकिल सवारों एवं विद्यार्थियों ने अपने जीवन में सतर्क रहने, ईमानदारी एवं नैतिक मूल्यों का पालन करने, भ्रष्ट आचरण से दूर रहने तथा भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज उठाने की शपथ ली। कार्यक्रम के माध्यम से यह संदेश दिया गया कि भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ाई केवल जांच एजेंसियों की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि प्रत्येक नागरिक की सक्रिय भागीदारी भी इसमें आवश्यक है।

इस जागरूकता रैली में आदर्श चौहान, प्रणय पंत, चित्रांग, अनमोल चौधरी, मोहम्मद हारिस, आदर्श रावत, मनिंदर सिंह, हरिसिमरन सिंह, अमन, आरती, सुरिंदर कुमार, जयन्ती प्रसाद गौड़, रामपाल, अक्षय, चंदन, वैभव एवं यश सहित अन्य प्रतिभागियों ने भाग लिया।

कार्यक्रम के माध्यम से आम नागरिकों से अपील की गई कि वे भ्रष्टाचार के प्रति उदासीन न रहें, अनैतिक गतिविधियों का विरोध करें तथा भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायतों एवं सूचनाओं को उचित आधिकारिक माध्यमों से संबंधित एजेंसी तक पहुंचाएं। नागरिकों को अपने व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में सत्यनिष्ठा, ईमानदारी और जवाबदेही के मूल्यों को अपनाने के लिए भी प्रेरित किया गया।

पीआरडी जवानों को 365 दिन का नियमित रोजगार दिया जायेः रावत

संवाददाता



देहरादून। प्रान्तीय रक्षक दल हित संगठन के प्रदेश अध्यक्ष किशन सिंह रावत ने कहा कि पीआरडी जवानों को वर्षभर 365 दिन का नियमित रोजगार दिया जाये।

आज यहां परेड ग्राउंड स्थित एक क्लब में पत्रकारों से वार्ता करते हुए किशन सिंह रावत ने कहा कि संगठन के द्वारा 18 मार्च 2026 से एकता विहार सहस्त्रधारा रोड में अनिश्चित कालीन धरना दिया जा रहा था। 6 जुलाई को विभागीय मंत्री श्रीमती रेखा आर्या को मांगों के संबंध में ज्ञापन दिया गया। मंत्री के निर्देश पर संयुक्त निर्देश युवा कल्याण एवं प्रातीय रक्षक दल द्वारा धरना स्थल पर संगठन से वार्ता की गयी तथा मांगों पर शीघ्र सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया गया। इसी आश्वासन के बाद 7 जुलाई से धरना स्थगित किया गया था। उन्होंने कहा कि उनकी दो मांगे है होमागार्ड की तर्ज पर मूल वेतन के साथ महंगाई भत्ता लागू किया जाए तथा पीआरडी जवानों को वर्षभर 365 दिन नियमित रोजगार दिया जाये। उन्होंने कहा कि संगठन को आश्वासन दिया गया था कि आगामी दो कैबिनेट बैठकों के भीतर मांगों को कैबिनेट के समक्ष रखा जायेगा लेकिन सात कैबिनेट बैठकें हो जाने के बावजूद अभी तक इन मांगों को कैबिनेट में प्रस्तुत नही किया गया जिससे प्रदेशभर के पीआरडी जवानों में भारी निराशा है।

उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी दो मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो प्रदेशभर के पीआरडी जवान लोकतांत्रिक एवं व्यापक आंदोलन के लिए बाध्य होंगे इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी विनोद तोमर, महासचिव वीर सिंह रावत, जिलाध्यक्ष नीवन सिंह बिष्ट आदि लोग मौजूद रहे।

नि:शुल्क हृदय रोग निदान शिविर का आयोजन



संवाददाता

देहरादून। श्री सत्य साईं सेवा संगठन, उत्तराखंड की ओर से रायपुर चौक स्थित साई ग्रेस एकेडमी इंटरनेशनल में नि:शुल्क हृदय रोग निदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने पहुंचकर कार्यक्रम में सहभागिता की। इस अवसर पर श्री सत्य साईं हार्ट हॉस्पिटल, अहमदाबाद एवं राजकोट (गुजरात) के विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम ने मरीजों की हृदय संबंधी जांच की और आवश्यक चिकित्सकीय परामर्श प्रदान किया।

इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा ने कहा कि जरूरतमंद लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना समाज के प्रति हम सभी की जिम्मेदारी है। हृदय रोग जैसी गंभीर बीमारियों की समय रहते पहचान और उपचार बेहद जरूरी है। श्री सत्य साईं सेवा संगठन की ओर से किया जा रहा यह प्रयास सराहनीय है।

◆ शिविर में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने की सहभागिता

कार्यक्रम का आयोजन श्री सत्य साईं सेवा संगठन, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष कर्नल योगेंद्र सिंह (वेटरन), डॉ समरजीत सिंह के नेतृत्व में किया गया। श्री सत्य साईं सेवा संगठन द्वारा आयोजित इस जनकल्याणकारी पहल का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद लोगों तक बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाना है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा और सुबोध उनियाल की उपस्थिति ने आयोजन में सहभागिता दर्ज कराई।

चीता पुलिस को पीटा 'पागल' ने

संवाददाता

देहरादून। चीता पुलिस को पल्टन बाजार में पागल ने पीट दिया। दोनों अस्पताल में भर्ती हुए। आज दोपहर को धारा चौकी क्षेत्र के चीता सिपाही पल्टन बाजार में गश्त कर रहे थे। इसी दौरान एक पागल ने उनपर हमला कर दिया और दोनों की जमकर पिटाई कर दी। जिससे आसपास के लोगों ने चीता पुलिस को पागल के चंगुल से बचाया और दोनों को दून अस्पताल में भर्ती कराया। पागल के हमले के बाद से क्षेत्र में दहशत का माहौल बना हुआ है। पुलिस पर हमले के बाद भी पागल पुलिस के हाथ नहीं लगा। जिसकी तलाश जारी है।

सू- दोकू क्र.077

		3					7	
9				6		3		8
	7		9		5		6	
						1		9
3		8		7			5	
	1		3		9			7
		2		8		7		
	8				2		4	3
			1					

नियम

1. कुल 81 वर्ग है,जिसमें 9वर्गो का एक खंड बनता है।
2. हर खाली वर्ग में 1से 9 के बीच का कोई एक अंक र सकते है।
3. बाएं से दाएं और उपर से नीचे के प्रत्येक कालम,कतार और खंड में 1से9अंक में से किसी भी अंक का इस्तेमाल एक बार ही कर सकते है।

सू-दोकू क्र.76 का हल

5	2	4	9	6	7	8	1	3
3	6	7	4	1	8	2	9	5
8	1	9	3	2	5	4	6	7
6	3	5	1	9	4	7	2	8
7	9	8	5	3	2	6	4	1
2	4	1	7	8	6	5	3	9
4	5	3	6	7	9	1	8	2
9	8	6	2	5	1	3	7	4
1	7	2	8	4	3	9	5	6

कुंभ-2027 : शिविर स्थलों से घाटों और संपर्क मार्गों तक तैयारियों को गति देने पर जोर

हरिद्वार(आरएनएस)। कुंभ मेला-2027 के आयोजन को सुव्यवस्थित, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए मेला प्रशासन द्वारा शिविर स्थलों से लेकर घाटों, पुलों और संपर्क मार्गों तक आवश्यक व्यवस्थाओं को समयबद्ध ढंग से विकसित किया जा रहा है। इसी क्रम में मेलाधिकारी श्रीमती सोनिका ने बैरागी कैंप, नया टापू, सती द्वीप और दक्ष द्वीप सहित कनखल क्षेत्र का विस्तृत स्थलीय निरीक्षण किया। उन्होंने विभिन्न शिविर स्थलों पर चल रहे अस्थायी कार्यों, घाटों के निर्माण एवं मरम्मत तथा आवागमन से जुड़ी परियोजनाओं की प्रगति का जायजा लेते हुए अधिकारियों को सभी कार्य गुणवत्ता के साथ निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के निर्देश दिए।

मेलाधिकारी ने बैरागी कैंप, सेक्टर-12 स्थित नया टापू, सती द्वीप एवं दक्ष द्वीप क्षेत्रों का भ्रमण कर कुंभ शिविरों के लिए की जा रही तैयारियों की जानकारी ली। उन्होंने शिविर स्थलों पर भूमि की सफाई, समतलीकरण एवं ड्रेसिंग के कार्यों की प्रगति देखने के साथ ही अस्थायी संपर्क मार्गों, बिजली और पेयजल आपूर्ति तथा सेक्टर प्लान के अनुरूप विकसित की जा रही अन्य आवश्यक सुविधाओं की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि सभी सेक्टरों में श्रद्धालुओं की सुगम आवाजाही, सुरक्षा और सुविधा को प्राथमिकता देते हुए आधारभूत व्यवस्थाएं समय से पूरी की जाएं। सेक्टर-12 के नया टापू तक पहुंचने वाले संपर्क मार्ग को बेहतर बनाने और मार्ग पर आवागमन की सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय सुनिश्चित करने के भी निर्देश दिए।

कुंभ मेला की मद से सतीघाट से बैरागी कैंप को जोड़ने के लिए 48 मीटर लंबे पैदल पुल का निर्माण किया जा रहा है। मेलाधिकारी ने इस निर्माण कार्य का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को गुणवत्ता सुनिश्चित करते हुए इसे शीघ्र पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने दक्ष द्वीप एवं बैरागी कैंप को जोड़ने के लिए निर्माणाधीन 60 मीटर स्पान के स्टील गर्डर डबल लेन पुल की प्रगति भी देखी और कार्य में तेजी लाने को कहा। इसके अतिरिक्त दरिद्रभंजन महादेव मंदिर के समीप मायापुर स्कैप चैनल पर प्रस्तावित बैली ब्रिज के स्थल का निरीक्षण करते हुए मेलाधिकारी ने निर्माण कार्य तत्काल प्रारंभ कराने के निर्देश दिए। उन्होंने इस पुल से कनखल क्षेत्र को जोड़ने वाली सड़क पर दरिद्रभंजन मंदिर और श्मशान घाट के प्रवेश द्वार के बीच स्थित संकरे हिस्से को चौड़ा करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। इसके लिए संबंधित भूस्वामियों से वार्ता कर आवश्यक भूमि उपलब्ध कराने की कार्यवाही करने के निर्देश दिए।

मेलाधिकारी ने बैरागी कैंप क्षेत्र में स्कैप चैनल पर निर्माणाधीन 260 मीटर लंबे घाट के कार्यों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कनखल क्षेत्र के विभिन्न सार्वजनिक घाटों का निरीक्षण कर उनकी स्थिति का आकलन किया। उन्होंने संबंधित विभागों को सभी घाटों की आवश्यक मरम्मत कराने के साथ ही स्नानार्थियों की सुरक्षा के लिए रेलिंग एवं चेन लगाने के निर्देश दिए।उन्होंने कहा कि स्कैप चैनल की बंदी की अवधि का उपयोग घाटों की समुचित सफाई और आवश्यक मरम्मत के लिए किया जाए। घाटों के बेहतर रखरखाव, सौंदर्यीकरण और नियमित सफाई की प्रभावी व्यवस्था सुनिश्चित की जाए, ताकि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं को स्वच्छ एवं सुरक्षित स्नान की सुविधा उपलब्ध हो सके।

मेलाधिकारी ने कनखल स्थित दक्ष मंदिर, शीतला माता मंदिर एवं दरिद्रभंजन मंदिर का भ्रमण कर क्षेत्र की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। साथ ही कनखल श्मशान घाट क्षेत्र में कुंभ मेला की मद से कराए जा रहे कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने श्मशान घाट की अवस्थापना सुविधाओं को सुदृढ़ करने के साथ ही प्रकाश व्यवस्था, पेयजल आपूर्ति, शौचालय निर्माण और जनसुविधाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता से पूरा करने के निर्देश दिए। भ्रमण के दौरान मेलाधिकारी ने स्थानीय नागरिकों से भी भेंटकर मेला की व्यवस्थाओं और कार्यों के संबंध में उनके फीडबैक और सुझाव प्राप्त किये। मेलाधिकारी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि कुंभ से संबंधित सभी निर्माण एवं व्यवस्थागत कार्यों की नियमित निगरानी की जाए। कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ ही संबंधित क्षेत्रों की आवश्यकता एवं उपयोगिता का भी विशेष ध्यान रखा जाए, ताकि कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं और स्थानीय नागरिकों को बेहतर सुविधाएं मिल सकें।

थराली अस्पताल में एक भी विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं

चमोली(आरएनएस)। पिंडरघाटी के एकमात्र सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) थराली में सात विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं। ऐसे में 40 हजार से अधिक की आबादी को इलाज के लिए 100 से 150 किलोमीटर दूर बागेश्वर या कर्णप्रयाग जाना पड़ता है।

यह सीएचसी अब उप जिला चिकित्सालय घोषित हो चुका है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में बाल रोग, स्त्री रोग, हड्डी रोग, नेत्र, ईएनटी और सर्जन सहित सात विशेषज्ञ डॉक्टरों के पद स्वीकृत हैं। हालांकि आज तक यहां किसी भी विशेषज्ञ डॉक्टर की तैनाती नहीं हुई है। व्यापार संघ अध्यक्ष संदीप रावत और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विनोद रावत ने इस स्थिति पर चिंता जताई।

उन्होंने कहा कि विशेषज्ञ डॉक्टरों के अभाव में कई बार मरीज दम तोड़ देते हैं। अस्पताल में अल्ट्रासाउंड की सुविधा और पर्याप्त जीवन रक्षक दवाएं भी उपलब्ध नहीं हैं।

स्थानीय लोगों ने विशेषज्ञ डॉक्टरों की तत्काल तैनाती की मांग की। वहीं अपर जिला मुख्य चिकित्सा अधिकारी अभिषेक गुप्ता ने बताया कि विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती के लिए शासन को पत्र भेजा गया है।

थराली में एक स्थायी और चार अनुबंध डॉक्टर तैनात किए गए हैं। यह तैनाती मौजूदा कमी को पूरा करने के लिए की गई है।

विकसित उत्तराखंड के लिए 2047 तक का रोडमैप तैयार करेंगे विभाग, सीडीओ ने मांगा विजन

हरिद्वार(आरएनएस)। वर्ष 2047 तक उत्तराखंड को विकसित, समृद्ध और आत्मनिर्भर राज्य बनाने के लक्ष्य को लेकर जिले में विभागीय स्तर पर दीर्घकालिक योजनाएं तैयार की जाएंगी। इसके लिए सभी विभागों को वर्तमान जरूरतों के साथ भविष्य की चुनौतियों और संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए विकास का रोडमैप तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य विकास अधिकारी डॉ. ललित नारायण मिश्र ने जिला कार्यालय सभागार में विभागीय अधिकारियों की बैठक लेकर उनके विभागों का विजन और प्रस्तावित योजनाओं की जानकारी ली। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में आयोजित बैठक में सीडीओ ने सभी विभागों से क्रमवार वर्तमान में संचालित योजनाओं के साथ भविष्य की संभावित योजनाओं पर चर्चा की।

उन्होंने अधिकारियों से पूछा कि वर्ष 2047 तक विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य हासिल करने के लिए उनके विभाग की क्या कार्ययोजना है और विकास की नई संभावनाओं को साकार करने के लिए कौन से नवाचार किए जा सकते हैं। सीडीओ ने कहा कि विकसित उत्तराखंड का लक्ष्य हासिल करने के लिए विभागों को पारंपरिक कार्यप्रणाली से आगे बढ़कर नए विचारों और सकारात्मक सोच के साथ काम करना होगा। प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण, आधारभूत सुविधाओं का विस्तार, बेहतर संपर्क व्यवस्था, स्वच्छ ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और नागरिक केंद्रित सुशासन जैसे क्षेत्रों में दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ काम करना जरूरी है। बैठक में मुख्य चिकित्साधिकारी डॉ. आरके सिंह, जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक अभिषेक शुक्ला, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी सतीश जोशी, महाप्रबंधक उद्योग उत्तम कुमार तिवारी, जिला पंचायत राज अधिकारी अतुल प्रताप सिंह, जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी नलिनी ध्यानी, जिला पर्यटन अधिकारी सुशील नौटियाल, जिला सैनिक कल्याण अधिकारी विंग कमांडर डॉ. सरिता नेगी, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी निखिल शर्मा सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

नाबालिग बेटी से अश्लील हरकत के आरोप में पिता गिरफ्तार

हमारे संवाददाता

हरिद्वार। धर्मनगरी हरिद्वार में रिश्तों को शर्मसार करने का एक गंभीर मामला सामने आया है। एक महिला ने अपने पति पर 16 वर्षीय नाबालिग बेटी के साथ अश्लील और आपत्तिजनक हरकतें करने का आरोप लगाया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी पिता के खिलाफ पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के अनुसार महिला ने आरोप लगाया कि उसका पति पिछले करीब एक साल से उनकी 16 वर्षीय बेटी के साथ अश्लील और आपत्तिजनक हरकतें कर रहा था। महिला का कहना है कि विरोध करने और कई बार समझाने के बावजूद आरोपी अपनी हरकतों से बाज नहीं आया।

आरोप है कि आरोपी अपनी पत्नी और बच्चों के साथ आए दिन गाली-गलौज और मारपीट करता था। पिता की कथित हरकतों के कारण नाबालिग बेटी भय और मानसिक परेशानी में रहने लगी थी।

बताया जा रहा है कि पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपनी मां को आपबीती बताई। इसके बाद मां ने 31 अक्टूबर को कोतवाली पहुंचकर अपने पति के खिलाफ लिखित शिकायत दी और कार्रवाई की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तत्काल मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। जिसे पुलिस टीम ने तलाश करते हुए उसके किराये के मकान से गिरफ्तार कर लिया है।

जनगणना-2027 के संबंध में किसी भी भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें: निदेशक

हमारे संवाददाता

देहरादून। भारत की जनगणना-2027 के संबंध में जारी नवीन राजपत्र अधिसूचना के कारण आमजन के मध्य जनगणना के कार्यक्रम को लेकर कुछ भ्रांतियां उत्पन्न हुई हैं।

इस संबंध में निदेशक, इवा आशीष श्रीवास्तव, जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तराखण्ड ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखण्ड राज्य में भारत की जनगणना-2027 का कार्य पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार दिनांक 01 दिसम्बर, 2026 से 4 जनवरी, 2027 तक आयोजित किया जाएगा। इसके पूर्व नागरिकों को स्व-गणना की सुविधा दिनांक 16 नवम्बर, 2026 से 30 नवम्बर, 2026 तक उपलब्ध रहेगी। भारत के अन्य, गैर-निर्वाचन राज्यों के लिए जारी नवीन अधिसूचना के संबंध में प्रसारित समाचार को उत्तराखण्ड के जनगणना कार्यक्रम से जोड़कर देखा जाना उचित नहीं है।

उत्तराखण्ड में जनगणना के निर्धारित कार्यक्रम में कोई परिवर्तन अथवा स्थगन नहीं किया गया है। अत: सभी नागरिकों एवं संबंधित अधिकारियों से अनुरोध है कि जनगणना-2027 के संबंध में किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना पर ध्यान न दें तथा केवल अधिकृत माध्यमों से प्राप्त सूचना पर ही विश्वास करें।

चुनावी रंग में रंगी देवभूमि...

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

मुकाबले का असर प्रदेश के अन्य राजनीतिक दलों पर भी पड़ेगा। उत्तराखंड क्रांति दल सहित क्षेत्रीय राजनीतिक शक्तियां राज्य की मूल अवधारणा, पहाड़ी अस्मिता, रोजगार, भू-कानून, पलायन और स्थानीय संसाधनों पर अधिकार जैसे मुद्दों को लेकर अपनी जगह तलाश सकती हैं। हालांकि, इन मुद्दों पर जनसमर्थन को चुनावी सफलता में बदलने के लिए उन्हें भी मजबूत संगठन, स्पष्ट नेतृत्व और विधानसभा क्षेत्रों में प्रभावी उपस्थिति दिखानी होगी। भाजपा-कांग्रेस के बीच सीधा मुकाबला होने की स्थिति में तीसरे विकल्प के लिए राजनीतिक जगह बनाना आसान नहीं होगा, लेकिन क्षेत्रीय सवालों पर जनता की नाराजगी किसी भी दल के लिए अवसर पैदा कर सकती है।

फिलहाल इतना साफ है कि उत्तराखंड में वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव की लड़ाई का शुरुआती चरण शुरू हो चुका है। कांग्रेस न्याय के सवालों को चुनावी हथियार बनाना चाहती है, तो भाजपा लोकतंत्र और व्यवस्था के सवालों के जरिए विपक्ष को घेर रही है। दोनों दलों ने अपने-अपने मोर्चे खोल दिए हैं। अब देखना यह होगा कि यह सियासी संग्राम नारों और यात्राओं तक सीमित रहता है या जनता के वास्तविक मुद्दों को केंद्र में लाकर प्रदेश की राजनीति को नई दिशा देता है।

2027 की जंग के लिए यूकेडी का..

◀◀ पृष्ठ 2 का शेष

उम्मीदवारों के चयन में पारदर्शिता दिखाती है, तो वह क्षेत्रीय राजनीति के लिए जगह बना सकती है। इसके विपरीत, यदि युवा चेहरों को आगे करने की पहल केवल चुनावी घोषणा तक सीमित रही, तो इसका असर सीमित रह सकता है।

कुल मिलाकर, यूकेडी का युवा दांव उत्तराखंड की क्षेत्रीय राजनीति में नई संभावना पैदा कर सकता है, लेकिन इसकी सफलता का पैमाना केवल युवा चेहरों की मौजूदगी नहीं होगा। असली कसौटी यह होगी कि पार्टी राज्य आंदोलन की विरासत को रोजगार, पलायन, भू-कानून, स्थानीय संसाधनों और पहाड़ी विकास जैसे मौजूदा सवालों से कितनी मजबूती से जोड़ती है। वर्ष 2027 में यूकेडी भाजपा-कांग्रेस के मुकाबले कितनी जगह बना पाती है, यह उसके युवा नेतृत्व की स्वीकार्यता के साथ-साथ संगठनात्मक मजबूती और चुनावी तैयारी पर भी निर्भर करेगा।

सालावाला में बनेगा 20 मीटर लंबा डबल लेन पुल

हमारे संवाददाता

देहरादून। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने आज मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सालावाला में राज्य योजना वर्ष 2026-27 के तहत न्यू कैंट रोड स्थित सालावाला पुल के डाउनस्ट्रीम में 20 मीटर लंबे दो लेन आरसीसी गर्डर पुल के निर्माण कार्य का विधिवत शिलान्यास किया। इस पुल का निर्माण 541.28 लाख रूपये की लागत से किया जाएगा।



इस अवसर पर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि क्षेत्र में आवागमन को सुगम, सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए यह पुल महत्वपूर्ण साबित होगा। पुल के निर्माण से स्थानीय निवासियों सहित यहां से आवागमन करने वाले लोगों को बेहतर यातायात सुविधा मिलेगी और क्षेत्र में यातायात व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार जनसुविधाओं के विस्तार और आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

अधिकारियों द्वारा बताया गया कि पुल का निर्माण कार्य आगामी 8 माह के भीतर पूर्ण कर लिया जाएगा। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने निर्माण कार्य को निर्धारित समयसीमा के अंतर्गत गुणवत्ता के साथ पूरा करने के सम्बन्धित विभाग के अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष प्रदीप रावत, पार्षद भूपेंद्र कठैत, पार्षद मोहन बहुगुणा, रोशन नेगी, रमेश प्रधान, राकेश कुमार, आनंद गुसाई सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे।

कमेटी के नाम पर चार लाख रुपये की ठगी में पति पत्नी नामजद

संवाददाता

देहरादून। कमेटी के नाम पर चार लाख रूपये की ठगी के मामले में पुलिस ने पति पत्नी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बद्रीपुर तिलवाडी निवासी हरबंश लाल ने नेहरू कालोनी थाने में मुकदमा दर्ज कराते हुए बताया कि उसकी पहचान हरिपुर नवादा निवासी जुल्फिकार अहमद व उसकी पत्नी नरगिस से हुई। दोनों ने बताया कि वह कमेटी का काम करते है। जिसके बाद उसने उनके यहां कमेटी डाल दी। जब उसने अपनी कमेटी के चार लाख रूपये मांगे तो उन्होंने देने से इंकार कर दिया और उसके साथ गाली गलौच करते हुए जान से मारने की धमकी दी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

लाखों रुपये की चरस सहित दो तस्कर दबोचे

हमारे संवाददाता

टिहरी। पहाड़ों में नशा तस्करी कर रहे दो लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जिनके पास से 708 ग्राम चरस बरामद हुई है।

जानकारी के अनुसार बीते रोज कोतवाली कैम्पटी पुलिस को सूचना मिली कि क्षेत्र में कुछ नशा तस्कर नशीले पदार्थो की डिलीवरी हेतू आने वाला है। सूचना पर कार्यवाही करते हुए पुलिस ने क्षेत्र में चैकिंग अभियान चला दिया। इस दौरान पुलिस को चौकी नैनबाग क्षेत्रान्तर्गत सिलासु पुल के पास दो संदिग्ध व्यक्ति आते हुए दिखायी दिये। पुलिस ने जब उन्हे रूकने का इशारा किया तो वह सकपका कर भागने लगे।



इस पर उन्हे घेर कर दबोचा गया। तलाशी के दौरान उनके पास से 708 ग्राम चरस बरामद हुई। पूछताछ में उन्होने अपना नाम अखिलेश चौहान पुत्र शैलेंद्र सिंह, निवासी ग्राम देवजानी, थाना मोरी, जनपद उत्तरकाशी व राजमोहन पुत्र शूरवीर सिंह, निवासी ग्राम देवजानी, थाना मोरी, जनपद उत्तरकाशी बताया। पुलिस ने उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हे अदालत में पेश किया जहां से उन्हे जेल भेज दिया गया है। बरामद चरस की कीमत 1 लाख 77 हजार रूपये बतायी जा रही है।

सहसपुर विधायक ने किया विभिन्न विकास कार्यो का शिलान्यास

संवाददाता

देहरादून। विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर ने विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर शिलान्यास किया।

आज यहां सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झाझरा में विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर ने विभिन्न विकास कार्यों का विधिवत पूजा-अर्चना कर शिलान्यास किया। इन कार्यों में ग्राम क्षेत्र के आंतरिक मार्गों पर इंटरलॉकिंग टाइल्स सड़क निर्माण एवं बालाजी मंदिर के सम्मुख मुख्य सड़क के सुधारीकरण का कार्य सम्मिलित है। इस अवसर पर विधायक सहदेव सिंह पुण्डीर ने कहा कि क्षेत्रवासियों की लंबे समय से महसूस की जा रही आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए इन विकास कार्यों को स्वीकृति प्रदान कर धरातल पर उतारा जा रहा है।



उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की योजना बनाते समय स्थानीय निवासियों की आवश्यकताओं एवं जनअपेक्षाओं को विशेष महत्व दिया जा रहा है, ताकि प्रत्येक क्षेत्र को बेहतर आधारभूत सुविधाओं का लाभ मिल सके।

उन्होंने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में प्रदेश सरकार विकास के संकल्प को निरंतर आगे बढ़ा रही है। प्रदेश सरकार के सहयोग से सहसपुर विधानसभा क्षेत्र में भी विभिन्न जनहितकारी योजनाओं एवं विकास कार्यों को गति मिल रही है। विधायक ने संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्यों में गुणवत्ता एवं निर्धारित मानकों का विशेष ध्यान रखने तथा कार्यों को समयबद्ध ढंग से पूर्ण करने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि जनसेवा, विकास और जनविश्वास के संकल्प के साथ सहसपुर विधानसभा क्षेत्र को विकास की नई ऊँचाइयों तक पहुँचाने के लिए उनके प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। इस दौरान क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, संगठन के पदाधिकरीगण एवं कार्यकर्ता समेत सम्मानित स्थानीय लोग मौजूद रहे।

सड़क पर आमने-सामने भाजपा-कांग्रेस

कार्यालय संवाददाता

देहरादून। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव की घोषणा में अभी वक्त है, लेकिन सियासी रणभेरी बज चुकी है। सत्ता के गलियारों से निकलकर राजनीति अब सड़कों पर पहुंच गई है। भाजपा और कांग्रेस के बीच टकराव अब केवल बयानों, प्रेसवार्ताओं और सदन की बहस तक सीमित नहीं रहा। दोनों दल जनता के बीच उतरकर अपनी ताकत दिखाने और विरोधी की घेराबंदी करने में जुट गए हैं।

वर्ष 2027 का विधानसभा चुनाव भले ही अभी कुछ महीने दूर हो, लेकिन दोनों प्रमुख दलों के लिए राजनीतिक तैयारी का यह समय बेहद अहम है। भाजपा के सामने सत्ता में लगातार तीसरी बार वापसी कर इतिहास रचने की चुनौती है, तो कांग्रेस के सामने सत्ता परिवर्तन की परंपरा को फिर से अपने पक्ष में करने और दस साल के अंतराल के बाद सरकार में लौटने का अवसर। इसीलिए सड़कों पर उतरने की यह कवायद केवल विरोध या समर्थन का प्रदर्शन नहीं, बल्कि चुनाव से पहले जनता की नब्ज टटोलने और राजनीतिक माहौल अपने अनुकूल बनाने की लड़ाई भी है।



उत्तराखंड की राजनीति में भाजपा इस समय सत्ता में है और उसका लक्ष्य वर्ष 2027 में लगातार तीसरी बार सरकार बनाना है। वर्ष 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में जीत के बाद पार्टी के सामने अब अपनी राजनीतिक पकड़ बनाए रखने की बड़ी चुनौती है। भाजपा के लिए यह चुनाव केवल सरकार के कामकाज पर जनमत संग्रह नहीं होगा, बल्कि संगठन की ताकत, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के प्रभाव की भी परीक्षा होगा। भाजपा का भरोसा अपने मजबूत संगठनात्मक ढांचे, बूथ स्तर तक फैले कार्यकर्ता नेटवर्क और केंद्र तथा राज्य सरकार की योजनाओं पर है। पार्टी विकास कार्यों, सड़क और बुनियादी ढांचे के विस्तार, धार्मिक पर्यटन तथा निवेश से जुड़े प्रयासों को जनता के बीच ले जाने की तैयारी में है।

◆उत्तराखंड में सत्ता के गलियारों से निकलकर राजनीति अब पहुंच गई सड़कों पर
◆सत्ता की हैट्रिक लगाने की तैयारी में भाजपा, वापसी के लिए कांग्रेस का संघर्ष
◆यात्राओं, नारों और शक्ति प्रदर्शन के बीच चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए दल

कांग्रेस के लिए वर्ष 2027 का चुनाव अपनी राजनीतिक प्रासंगिकता साबित करने का अवसर है। वर्ष 2017 और 2022 के विधानसभा चुनावों में हार के बाद पार्टी सत्ता से बाहर है। अब उसे भाजपा को चुनौती देने के साथ यह भी साबित करना है कि वह एकजुट होकर चुनाव लड़ने और सरकार चलाने का भरोसा पैदा कर सकती है। कांग्रेस के सामने सबसे बड़ा सवाल संगठनात्मक एकजुटता का है। प्रदेश में उसके पास अनुभवी नेताओं की कमी नहीं है, लेकिन इन नेताओं की राजनीतिक सक्रियता को एक साझा चुनावी रणनीति में बदलना जरूरी होगा। गुटबाजी, नेतृत्व को लेकर खींचतान और टिकटों की दावेदारी जैसे सवाल चुनाव नजदीक आने पर पार्टी के लिए मुश्किलें पैदा कर सकते हैं।

चुनाव से पहले दोनों दलों के वरिष्ठ नेताओं की सक्रियता बढ़ना स्वाभाविक है। भाजपा संगठन को मजबूत करने, कार्यकर्ताओं को चुनाव के लिए तैयार करने और सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने पर जोर दे रही है। कांग्रेस भी अपने संगठन को सक्रिय करने, जनसभाओं और यात्राओं के माध्यम से सरकार को घेरने तथा कार्यकर्ताओं में चुनावी ऊर्जा भरने की कोशिश कर रही है। आने वाले दिनों में राजनीतिक बयानबाजी और तेज होने के आसार हैं। एक दल का आरोप दूसरे दल के लिए जवाबी हमले का आधार बनेगा। स्थानीय स्तर पर नेताओं की सक्रियता, क्षेत्रीय समीकरण और संभावित उम्मीदवारों की दावेदारी भी राजनीतिक सरगर्मी बढ़ाएगी।

सड़कों पर शुरू हुआ यह सियासी संघर्ष अभी शुरुआती दौर में है। चुनाव की तारीख घोषित होने से पहले दोनों दल अपने समर्थकों को सक्रिय करने, विरोधियों की रणनीति का जवाब देने और जनता के बीच अपनी छवि मजबूत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन राजनीतिक यात्राओं, नारों और शक्ति प्रदर्शन से आगे बढ़कर जनता के वास्तविक सवालों का जवाब देना ही उनकी सबसे बड़ी परीक्षा होगी। युवाओं को रोजगार, पहाड़ों में पलायन पर रोक, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, महिलाओं की सुरक्षा, आपदा प्रबंधन और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने जैसे मुद्दे चुनावी बहस के केंद्र में आते हैं या नहीं, यह देखना महत्वपूर्ण होगा।

उत्तराखंड की 2027 की चुनावी जंग का पहला दौर सड़कों पर शुरू हो चुका है। भाजपा के लिए यह सत्ता की हैट्रिक का रास्ता तैयार करने की लड़ाई है, जबकि कांग्रेस के लिए सत्ता में वापसी की उम्मीदों को जमीन पर उतारने का मौका। दोनों दलों ने अपने राजनीतिक हथियार निकाल लिए हैं। अब मुकाबला इस बात का होगा कि कौन अपने नारों को जनता के भरोसे में और अपने शक्ति प्रदर्शन को वोटों में बदल पाता है।

देवप्रयाग विधायक कंडारी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, बाल-बाल बचे

हमारे संवाददाता

टिहरी। देवप्रयाग विधायक विनोद कंडारी की गाड़ी आज बदरीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर हादसे का शिकार हो गई। श्रीनगर से कीर्तिनगर की ओर जा रहे विधायक के वाहन को उफल्डा के समीप विपरीत दिशा से आ रहे एक अन्य वाहन ने जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मौके पर अफरा-तफरी मच गई। हादसे में विधायक विनोद कंडारी बाल-बाल बच गए।



जानकारी के अनुसार, विधायक विनोद कंडारी अपने वाहन से श्रीनगर से कीर्तिनगर की ओर जा रहे थे। इसी दौरान बदरीनाथ हाईवे पर उफल्डा के पास सामने से आ रहे एक वाहन ने उनके वाहन को टक्कर मार दी। हादसे में विधायक को हल्की चोटें आई हैं, वह सुरक्षित हैं।

आंगनबाडी कार्यकत्रियों का मुख्यमंत्री आवास कूच

संवाददाता

देहरादून। आंगनबाडी कार्यकत्रियों ने मुख्यमंत्री आवास कूच किया। जिनको राजपुर रोड पर पुलिस ने रोक दिया जिसके बाद वह वहीं पर धरने पर बैठ गयी।

आज यहां आंगनबाडी कार्यकत्रियां आंगनबाडी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले परेड ग्राउंड में एकत्रित हुए जहां से उन्होंने मुख्यमंत्री आवास के लिए कूच किया। वह परेड ग्राउंड से जैसे ही कनक चौक होते हुए राजपुर रोड पर पहुंचे तभी पुलिस ने बैरकेडिंग लगाकर उनको रोक दिया। जिसके बाद वहीं वहीं धरने पर बैठ गयी। जिसके बाद उन्होंने जिला प्रशासन के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। ज्ञापन में उन्होंने कहा कि उनके द्वारा पूर्व में भी आंगनबाडी कार्यकत्रियों एव



सहायिकाओं की अत्यंत गम्भीर एवं ज्वलंत समस्याओं से शासन को अवगत कराते आ रहे हैं। तीन मार्च को मुख्यमंत्री से वार्ता की गयी जिसमें उन्होंने आश्वासन दिया था कि मानदेय वृद्धि हेतु कमेटी गठित कर दी गयी है इसके उपरान्त सरकार का ध्यान आर्किषत करने हेतु दो दिसम्बर 2025 को सचिवालय रैली निकाली गयी, उच्चाधिकारियों ने लिखित आश्वासन दिया गया जल्द ही मानदेय वृद्धि हेतु कमेटी के निर्णय लिया जाने का आश्वासन दिया गया। उन्होंने कहा कि आंगनबाडी कार्यकत्रियां विगत अनेक वर्षो से विस्तारित कार्यक्षेत्र, डिजिटल, दायित्वए सर्वेक्षण पोषण मातृ शिशु कल्याण एवं विविध शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में सीमित संसाधनों के बावजूद पूर्ण निष्ठा से योगदान दे रही हैं। तथा 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर बिना पेंशन, बिना सामाजिक सुरक्षा अत्यंत चिन्ताजनक है।

इंसानियत शर्मसार! मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती गर्भवती

हमारे संवाददाता

नैनीताल। रामनगर में मानसिक रूप से अस्वस्थ 25 वर्षीय युवती के साथ कथित दुष्कर्म का गंभीर मामला सामने आया है। युवती के गर्भवती होने के बाद घटना का खुलासा हुआ। युवती ने होली के आसपास रामनगर में दो-तीन लोगों द्वारा दुष्कर्म किए जाने की बात बताई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और आरोपों की पुष्टि के लिए पड़ताल की जा रही है।

जानकारी के अनुसार, पिछले करीब आठ से नौ महीनों से युवती रामनगर के अलग-अलग क्षेत्रों में घूमती दिखाई दे रही थी। हाल ही में उसे काशीपुर रोडवेज बस अड्डे के पास दर्द से परेशान हालत में देखा गया। इसकी सूचना सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सुयाल को दी गई। सूचना मिलने पर मुकेश सुयाल अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और युवती



को चिकित्सकीय सहायता दिलाई। डॉक्टरों की जांच में युवती के गर्भवती होने की जानकारी सामने आई। युवती की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे तत्काल हल्द्वानी स्थित सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इसके साथ ही मामले की सूचना पुलिस को दी गई, ताकि घटना की जांच की जा सके और युवती को न्याय दिलाने के लिए आवश्यक कार्रवाई हो। सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सुयाल

◆दो-तीन लोगों पर गंभीर आरोप

के मुताबिक, युवती बातचीत के दौरान खुद को पौड़ी गढ़वाल का निवासी बता रही थी। मानसिक रूप से अस्वस्थ युवती ने होली के आसपास रामनगर में दो-तीन लोगों द्वारा उसके साथ दुष्कर्म किए जाने की बात कही। युवती के बयान के आधार पर पुलिस अब घटना से जुड़े तथ्यों और संभावित आरोपियों की जानकारी जुटा रही है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए पुलिस विभिन्न पहलुओं से जांच कर रही है। रामनगर कोतवाल सुशील कुमार ने बताया कि मामले की गंभीरता से जांच की जा रही है। महिला सेल को भी इसकी जानकारी दी जा रही है। जांच में जो भी व्यक्ति दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वहीं, सामाजिक कार्यकर्ता मुकेश सुयाल ने घटना पर रोष जताते हुए आरोपियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। फिलहाल पुलिस जांच जारी है। युवती के आरोपों की पुष्टि और घटना में शामिल लोगों की पहचान के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है।

आर.एन.आई.- 59626/94

स्वामी, प्रकाशक, मुद्रक श्रीमती पुष्पा कांति कुमार द्वारा दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग घंटाघर, देहरादून से प्रकाशित तथा अवि प्रिंटर्स 21 ईसी रोड, देहरादून से मुद्रित।

प्रधान संपादक
कांति कुमार

संपादक
पुष्पा कांति कुमार

समाचार संपादक
आनंद कांति कुमार

कानूनी सलाहकार:
वी के अरोड़ा, *एडवोकेट*
बैजनाथ, *एडवोकेट*

कार्यालय: दिग्विजय सिनेमा बिल्डिंग देहरादून।
मो. 9358134808

नोट: सभी विवादों के लिये देहरादून न्यायालय ही मान्य होगा, प्रकाशित सामग्री के लिए प्रिंटर्स की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।